सत्यमेव जयते
Government of India

आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF
ECONOMIC AFFAIRS

Map on the front cover page is a creative representation and is not to scale.

सत्यमेव जयते
Government of India

आर्थिक समीक्षा
2025-26
मुख्य विशेषताएं

आर्थिक समीक्षा 2025-26
मुख्य बातें

आर्थिक समीक्षा 2025-26 की 'मुख्य बातें' (हाइलाइट्स) दस्तावेज लगभग 45 पृष्ठों में चार्ट, इन्फोग्राफिक्स और न्यूनतम पाठ का उपयोग करके सोलह अध्यायों में से प्रत्येक के मुख्य पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह दस्तावेज समीक्षा का एक आकर्षक और आसानी से पढ़ने योग्य सिंहावलोकन प्रदान करता है, जो पाठकों को अधिक व्यापक समझ के लिए इसकी अंतर्वस्तु का गहन विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य पाठकों के बीच जिज्ञासा तथा अधिक अन्वेषण संबंधी भाव को बढ़ावा देते हुए, जटिल डेटा को सुलभ और प्रासंगिक बनाना है, चाहे वे नीति प्रणेता हों, छात्र हों या पेशेवर हों।

वी. अनंत नागेश्वरन
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

1.	अर्थव्यवस्था की स्थिति: विकास-सीमा का विस्तार	03
2.	राजकोषीय घटनाक्रम: विश्वसनीय समेकन के माध्यम से स्थिरता को सुदृढ़ करना	05
3.	मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: विनियामक स्पर्श को परिष्कृत करना	07
4.	वैदेशिक क्षेत्र: दूरगामी लक्ष्य की तैयारी	11
5.	मुद्रास्फीति: नियंत्रित और स्थिर	15
6.	कृषि और खाद्य प्रबंधन: उत्पादकता वृद्धि, आय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना	19
7.	सेवाएँ: स्थिरता से नए आयामों तक	21
8.	उद्योग का अगला चरण: संरचनात्मक परिवर्तन और वैश्विक एकीकरण	24
9.	निवेश और अवसंरचना: कनेक्टीविटी, क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता का सुदृढ़ीकरण	27
10.	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन: एक प्रतिरोधी, प्रतिस्पर्धी और विकास-संचालित भारत का निर्माण	30
11.	शिक्षा और स्वास्थ्य: उपलब्धियां और भविष्य की रूपरेखा	34
12.	रोजगार और कौशल विकास: उन्नत कौशल की ओर	36
13.	ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति: भागीदारी से साझेदारी तक	39
14.	भारत में एआई व्यवस्था/पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) का विकास: आगे की दिशा	40
15.	नागरिक-केंद्रित शहरीकरण: भारतीय शहरों की अगली चुनौती	43

1 अर्थव्यवस्था की स्थितिः विकास-सीमा का विस्तार

वैश्विक नीति अब दक्षता या बहुपक्षीय नियमों की तुलना में सुरक्षा और राजनीतिक विचारों से अधिक प्रभावित हो रही है।

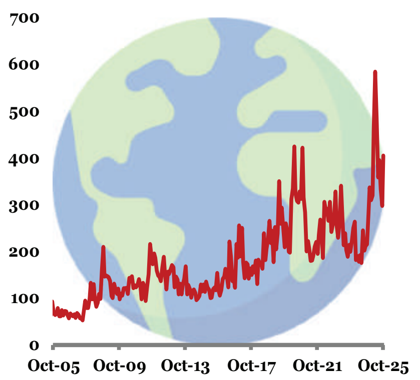

- भू-राजनीतिक संघर्षों में तीव्रता
- ऊर्जा और वित्त का रणनीतिक उपयोग
- प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण
- मुक्त व्यापार के प्रति संदेह
- महत्वपूर्ण खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा

विश्वभर में प्राथमिक संतुलन (% जीडीपी) में गिरावट

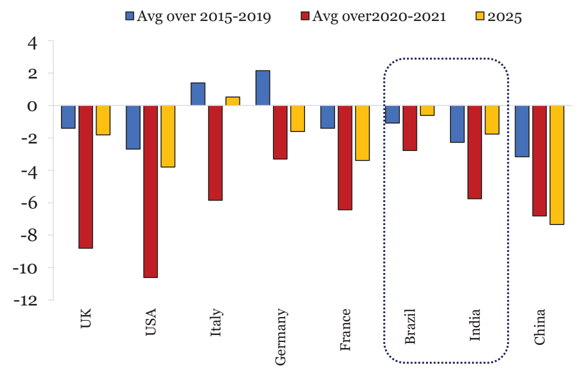

विश्व भर में संप्रभु यील्ड में वृद्धि

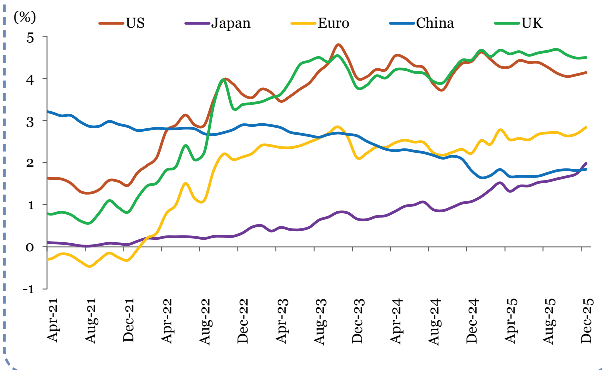

भारत ने मजबूत विकास गति बनाए रखी, वित्त वर्ष 27 में 6.8-7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान

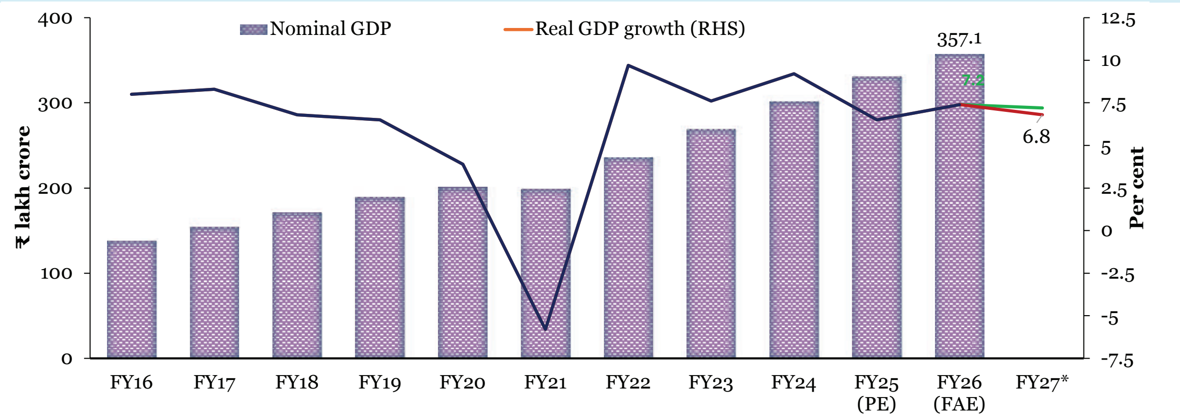

भारत की वृद्धि में निजी खपत और निवेश मुख्य चालक

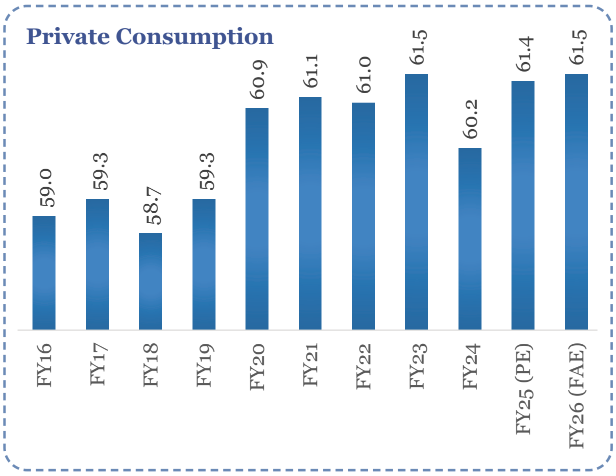

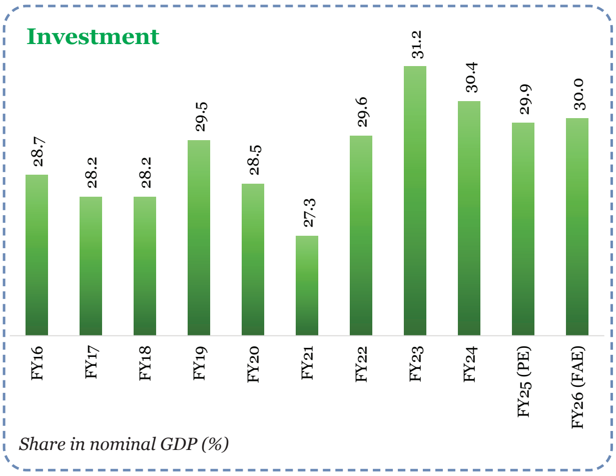

वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (%) में व्यापक आधारित वृद्धि

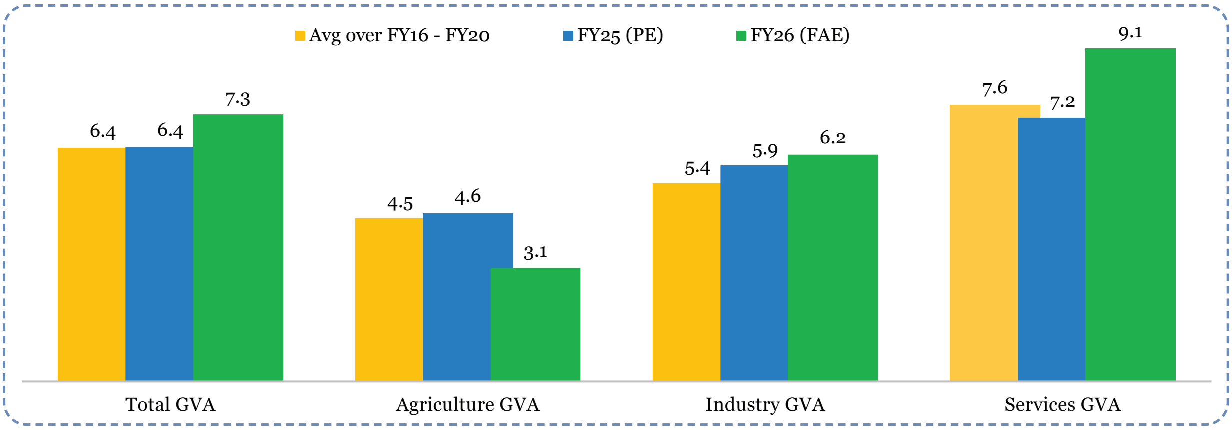

रिफॉर्म एक्सप्रेस से भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि ~7% तक पहुँची

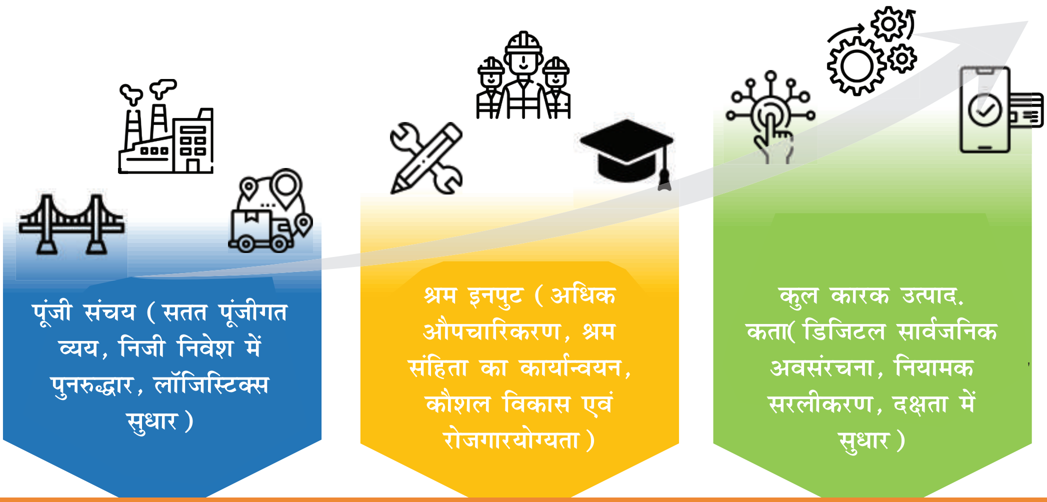

मैक्रोइकॉनॉमिक आधार और सतत सुधार

2 राजकोषीय घटनाक्रमः विश्वसनीय समेकन के माध्यम से स्थिरता को सुदृढ़ करना

समष्टि आर्थिक स्थिरता और विश्वास के एक प्रमुख आधार के रूप में राजकोषीय नीति

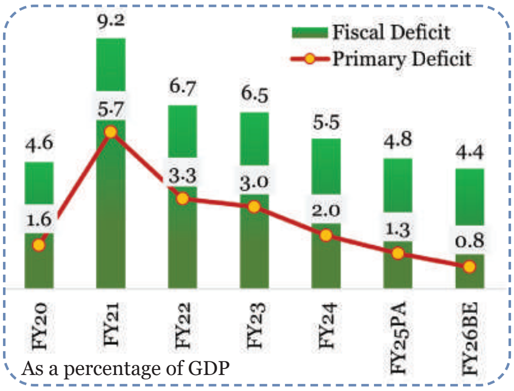

सार्वभौमिक क्रेडिट रेटिंग उन्नयन (2025) के पीछे प्रमुख प्रेरक के रूप में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन

- मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस
- एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स
- अनुसंधान एवं नवाचार, जापान

राजस्व में बेहतर उछाल

पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर

बेहतर राजकोषीय पारदर्शिता

एक विश्वसनीय मार्ग के साथ निरंतर घाटे में कमी

राजस्व में निरंतर वृद्धि और प्रत्यक्ष कर आधार का विस्तार

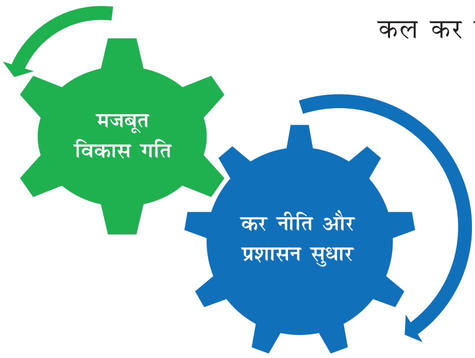

कल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि

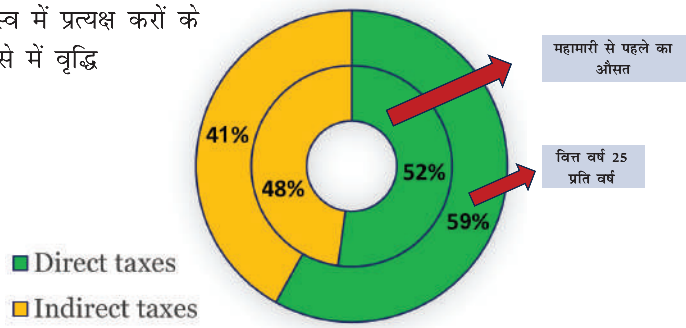

	राजस्व प्राप्तियाँ / सकल घरेलू	सकल कर राजस्व / जीडीपी	गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह/जीडीपी		आयकर रिटर्न दाखिल
महामारी के बाद औसत (वित्त वर्ष 22-वित्त वर्ष 25)	9.1%	11.5%	3.3%	2024-25	9.2 करोड़
महामारी से पहले का औसत महामारी पूर्व औसत (वित्त वर्ष 16-वित्त वर्ष 20)	8.5%	10.8%	2.4%	2021-22	6.9 करोड़

जीएसटी के तहत लेन-देन की मजबूत गति, तब भी जब सकल जीएसटी संग्रह नाममात्र (नॉमिनल) सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप है

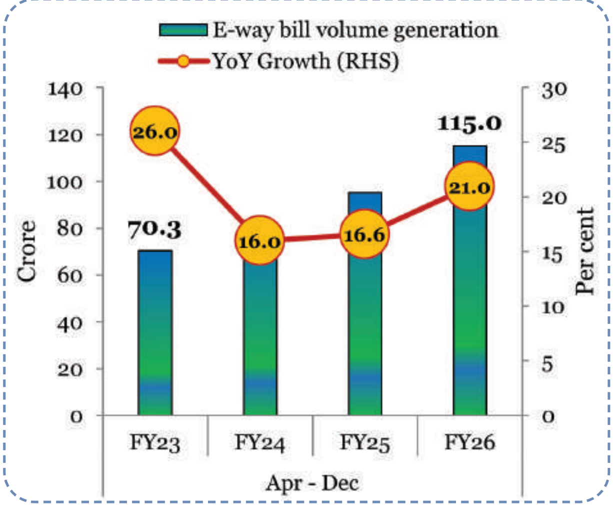

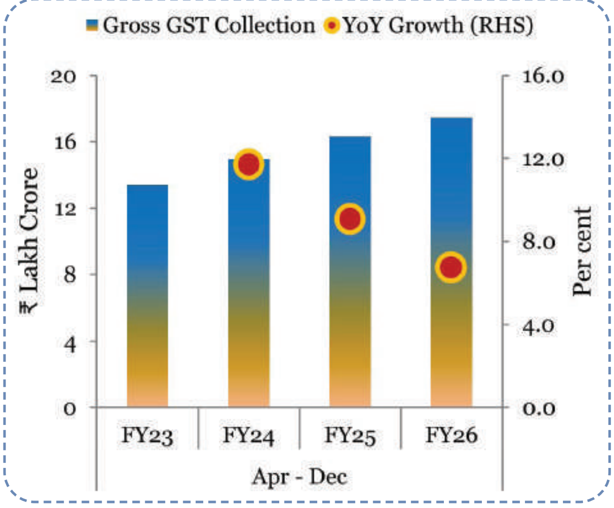

जीएसटी 2.0 सुधार और प्रभाव

दो-दर संरचना

18% मानक और 5% योग्यता

40% अवगुण/अहितकर वस्तुएं (उपकर सहित)

प्रभाव के अपेक्षित चौनल

खपत में वृद्धि
सरलीकृत अनुपालन, घरेलू उपभोग को समर्थन, व्यापक कर आधार।

विनिर्माण और व्यापार
विनिर्माण को बढ़ावा देना, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, छोटे व्यवसायों को औपचारिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करना

संरचनात्मक सुधार
उल्टी शुल्क संरचना का समाधान करना, कार्यशील पूंजी में सुधार

केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) जीडीपी के अनुपात में महामारी से पहले के औसत 2.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 4% हो गया।

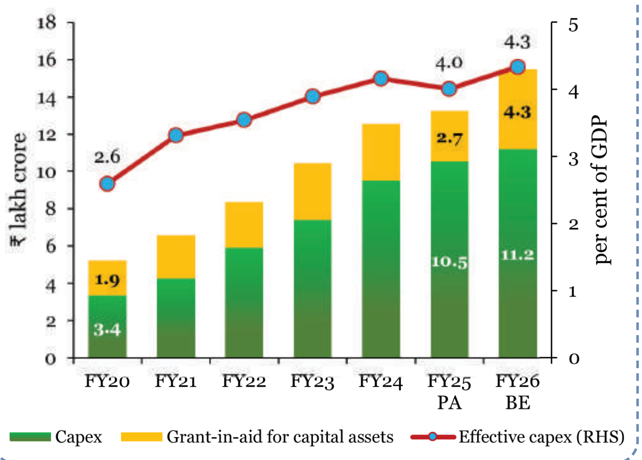

केंद्र सरकार की एसएएससीआई योजना ने राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.4% पर पूंजीगत व्यय बनाए रखने के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहित किया।

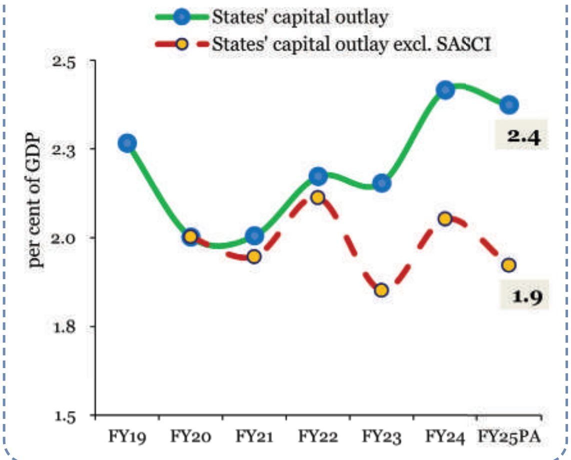

3 मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: विनियामक स्पर्श को परिष्कृत करना

मुद्रा और ऋण बाजारों में मौद्रिक नीति का प्रभावी अंतरण

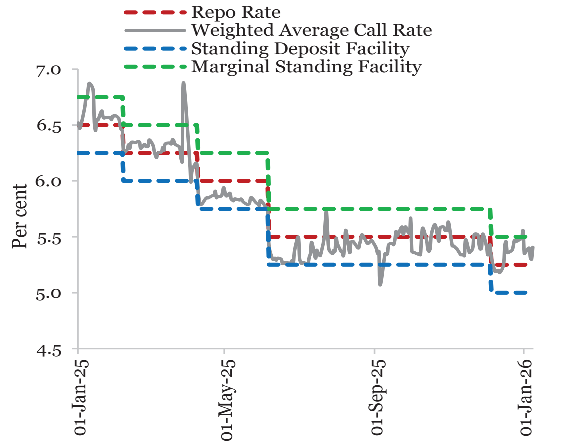

भारित औसत कॉल दर (मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य) वित्त वर्ष 2026 में नीतिगत रेपो दर से नीचे रही, जो 8 जनवरी 2025 तक औसत 8 बीपीएस (bps) कम थी।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

मौद्रिक घटनाक्रम वित्तीय स्थितियों में सहजता को दर्शाते हैं।

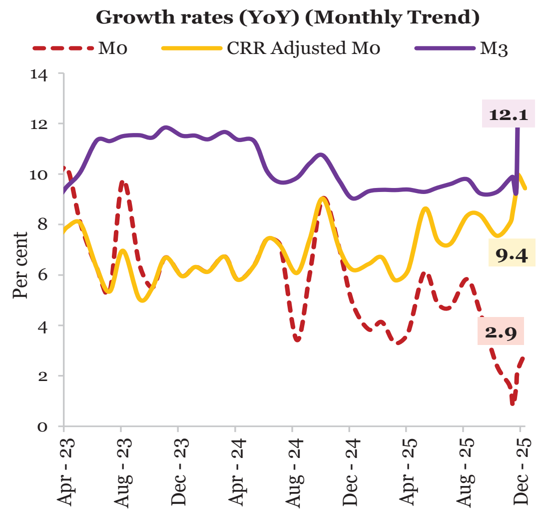

नोट: M0 – प्रारक्षित मुद्रा, M3 – स्थूल मुद्रा

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मिलने वाले बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि का रुझान जारी है।

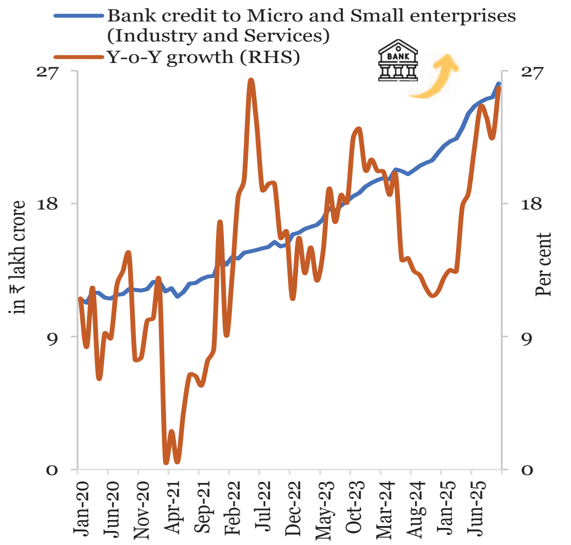

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार : कई दशकों के न्यूनतम स्तर पर जीएनपीए और एनएनपीए

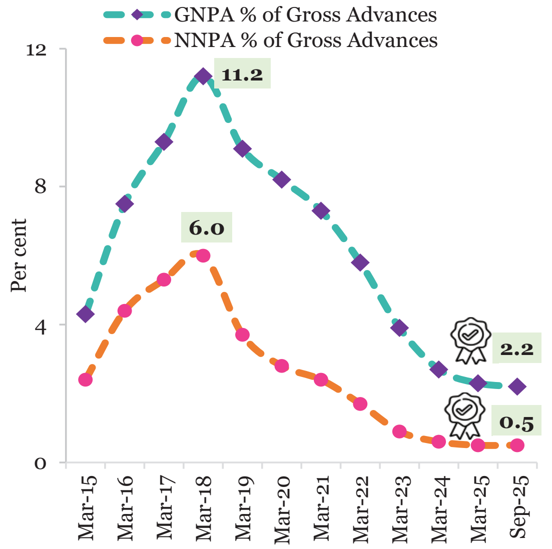

एससीबी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; जीएनपीएस: सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ; एनएनपीए: निवल एनपीए

स्रोत: आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

पेंशन कवरेज का विस्तार

अटल पेंशन योजना | **राष्ट्रीय पेंशन योजना**

वित्त वर्ष 16

अटल पेंशन योजना		राष्ट्रीय पेंशन योजना	
24.6 लाख सब्सक्राइबर	प्रबंधित परिसंपत्तियाँ (एयूएम): 0.51 हजार करोड़	97.5 लाख सब्सक्राइबर	प्रबंधित परिसंपत्तियाँ (एयूएम): 118.3 हजार करोड़

वित्त वर्ष 25

अटल पेंशन योजना		राष्ट्रीय पेंशन योजना	
641.3 लाख सब्सक्राइबर	प्रबंधित परिसंपत्तियाँ (एयूएम): 44.8 हजार करोड़	198.6 लाख सब्सक्राइबर	प्रबंधित परिसंपत्तियाँ (एयूएम): 1398.7 हजार करोड़

स्रोत: पीएफआरडीए

नोट: एयूएम-प्रबंधन के अंतर्गत परिसम्पत्ति

सभी के लिए बीमा सुरक्षा

जीवन और सामान्य बीमा प्रीमियम की कुल राशि में वृद्धि हो रही है।

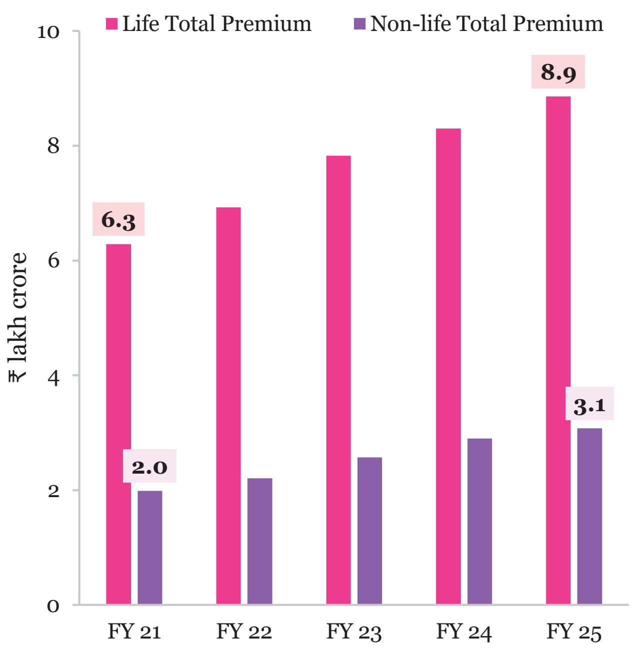

वित्त वर्ष 2025 में प्रबंधित परिसम्पत्तियां: ₹77.4 लाख करोड़

वित्त वर्ष 25.- कुल प्रीमियम आय वित्त वर्ष 2021 के 8.3 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹11.9 लाख करोड़ हो गई।

जीवन बीमाकर्ताओं ने वित्त वर्ष 2025 में कुल ₹6.3 लाख करोड़ के लाभ का भुगतान किया।

सामान्य बीमा क्षेत्र में निवल दावे वित्त वर्ष 2025 में ₹1.9 लाख करोड़ थे।

प्रगति विस्तार - मार्च 2025 तक बीमाकर्ताओं के कार्यालय: 22,076 - वितरण नेटवर्क: वित्त वर्ष 2025 तक 83 लाख भागीदार।

पूंजी बाजार में विकास: वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-नवंबर 2025)

प्राथमिक बाजारों से कुल संसाधन जुटाने (इक्विटी + ऋण) में निरंतर वृद्धि

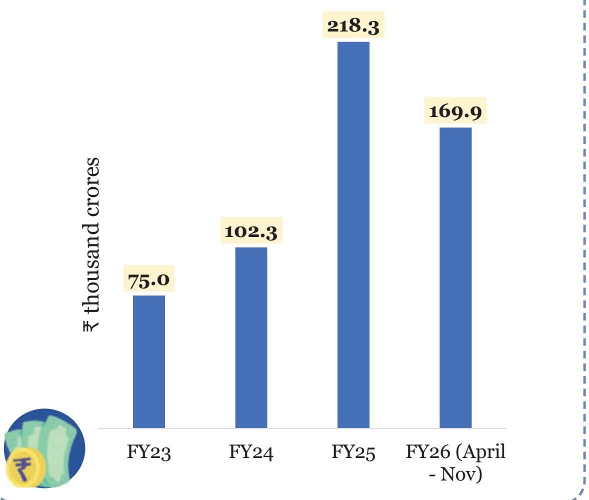

आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों की संख्या में वृद्धि

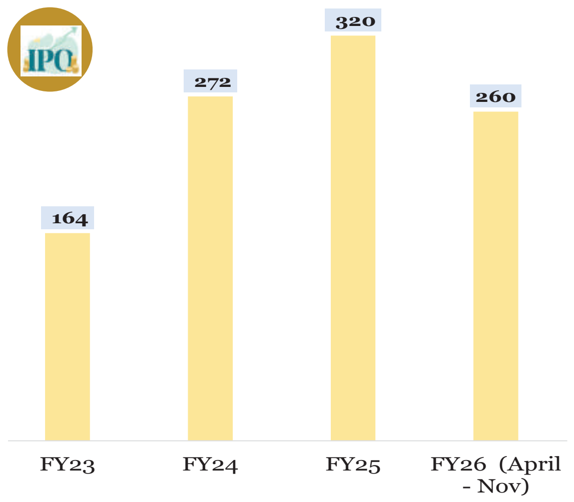

विनियामक परिवर्तन

बैंकिंग क्षेत्र

- विनियमों के निर्माण के लिए आरबीआई की अवसंरचना: यह समय-समय पर समीक्षा और परामर्श को अनिवार्य बनाते हुए विनियामक प्रक्रिया का मानकीकरण करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 9,000 से अधिक मौजूदा परिपत्रों और दिशा-निर्देशों को एकीकृत किया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बि.जनेस' को बढ़ावा देने हेतु एक नए 'क्रेडिट असेसमेंट मॉडल' (ऋण मूल्यांकन मॉडल) को प्रस्तुत किया है।
- आरबीआई का नि:शुल्क-एआई: वित्तीय विनियामकों और संस्थानों के लिए एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के जोखिमों का प्रबंधन करते हुए इसका लाभ उठाने हेतु एक संरचित दृष्टिकोण

पूंजी बाजार

- प्रतिभूति बाजार संहिता 2025, एससीआरए – 1956, सेबी अधिनियम 1992 और डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996 को निरस्त और प्रतिस्थापित करती है, जिससे भारत के प्रतिभूति बाजार कानूनों का एकीकरण होता है।
- सेबी ने निवेशक सुरक्षा उपकरण (सेबी चेक, सेबी बनाम स्कैम) लॉन्च किया, एक ईएसजी ऋण ढांचा प्रस्तुत किया, म्युनिसिपल बॉन्ड (नगर पालिका बॉन्ड) के एक्सेस का विस्तार किया, और बिजली डेरिवेटिव्स की शुरुआत की।

बीमा क्षेत्र

- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025 को 21 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। यह प्रतिभूति बाजार के कानूनों को एकल ढांचे में एकीकृत करता है।
- महत्वपूर्ण उपबंधों में उच्च एफडीआई सीमाएँ, बीमाकर्ता विनियमों का सरलीकरण, पालिसीधारक सुरक्षा को सुदृढ़ करना और बीमा प्रचालन को भारत के डिजिटल डेटा सुरक्षा ढांचे के अनुरूप बनाना शामिल है।

माइक्रो-क्रेडिट (सूक्ष्म ऋण) में प्रगति: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 'अवित्तपोषित को वित्तपोषित' करने का एक दशक।

55.45 करोड़ ऋण खातों के माध्यम से ₹36.18 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई। (अक्टूबर 2025 तक की स्थिति)

कुल सूक्ष्म ऋणों (Microloans) में से 69% ऋण महिला उद्यमियों द्वारा प्राप्त किए गए।

एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यकों के 33.4 करोड़ खातों में ₹15.6 लाख करोड़ वितरित किए गए।

पीएम स्वनिधि: सूक्ष्म-ऋण वितरण के माध्यम से भारत के रेहड़ी-पटरी वालों का सशक्तिकरण।

जीवन स्तर में सुधार

स्वनिधि लाभार्थियों की औसत वार्षिक व्यावसायिक आय में 2023 और 2025 के बीच 20% की वृद्धि हुई।

बेहतर आय के परिणामस्वरूप 39% परिवारों के आवास स्तर में सुधार हुआ है, 55% के लिए भोजन की उपलब्धता सहज हो गई।, 44% के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती हुई है, और 50% के लिए शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हुई है।

सशक्त अल्पसंख्यक

33% लाभार्थी महिलाएँ हैं, तथा 64% लाभार्थियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) शामिल हैं।

स्वस्थ ऋण मेट्रिक्स

पुनर्भुगतान में सुदृढ प्रदर्शन दिखाया गया, जहाँ अनुमानित एनपीए दर 10% से नीचे रही।

स्रोत: पीएम स्वनिधि प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट ख्र 2025। (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सहयोग से।)

4 वैदेशिक क्षेत्र: दूरगामी लक्ष्य की तैयारी

वैश्विक व्यापार गतिशीलता

उभरती व्यापार नीति गतिविधि

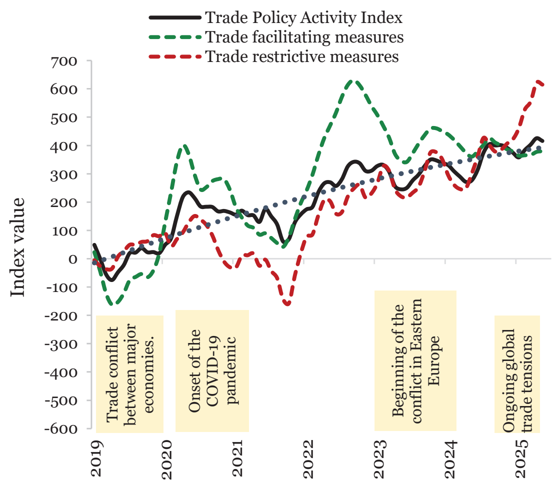

कैलेंडर वर्ष 2025 में, व्यापार नीति गतिविधि सूचकांक में वृद्धि मुख्य रूप से प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों में सहायक उपायों की तुलना में तेज वृद्धि के कारण हुई।

स्रोत: सेंटोरिनो, एस., आदि। (2025)। वैश्विक व्यापार नीति गतिविधि का मापन

व्यापार वृद्धि के रुझान (माल और सेवाएँ)

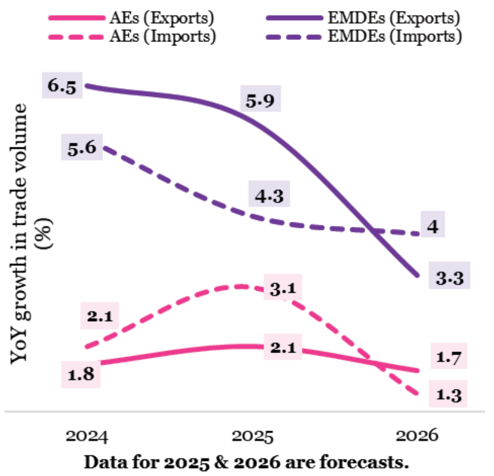

व्यापार नीति में अनिश्चितता का प्रभाव उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs) के व्यापार मात्रा पर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (AEs) की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है।

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अक्टूबर 2025), आईएमएफ

भारत का व्यापार प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2026 (अप्रैल-दिसंबर 2025) में

वैश्विक व्यापार अस्थिरता के बीच माल व्यापार मजबूत बना हुआ है

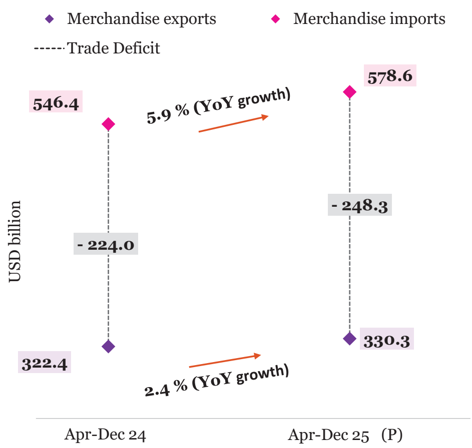

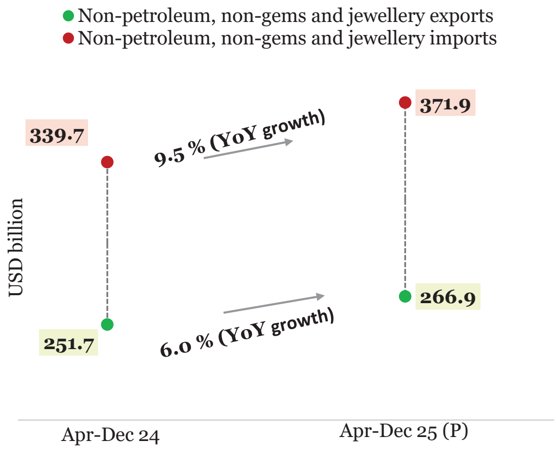

नोट: P : अनंतिम

स्रोत: वाणिज्य विभाग

सेवाओं के व्यापार ने भारत के व्यापार प्रदर्शन में एक प्रमुख चालक का रूप बनाए रखा है

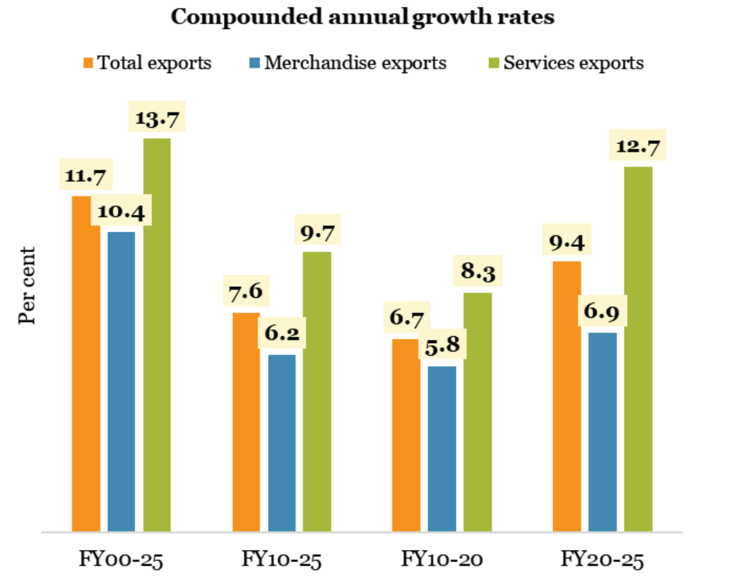

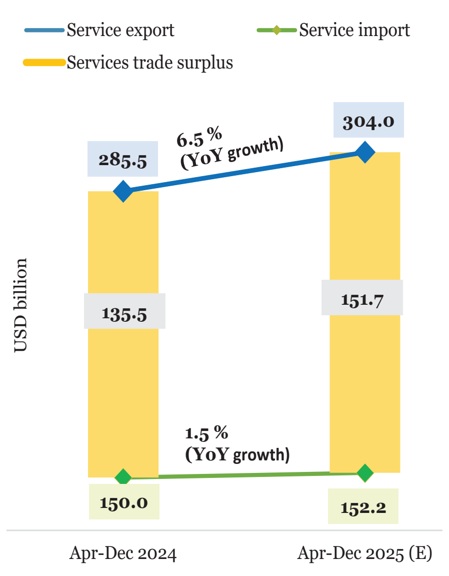

नोट: P : अनंतिम

स्रोत: वाणिज्य विभाग

भारत की व्यापार साझेदारियों का विस्तार करने की रणनीतिक पहल

8 Free Trade Agreements and Comprehensive Economic Partnerships Agreements concluded in the past 5 years

- India-Mauritius CECPA (2021)
- India-UAE CEPA (2022)
- India-Australia ECTA (2022)
- India-EFTA TEPA (2024)
- India-UK CETA (2025) — Yet to be implemented
- India-Oman CEPA (2025) — Yet to be implemented
- India-New Zealand FTA (2025) — Negotiations concluded
- India - European Union FTA — Negotiations concluded

Free Trade Agreements under negotiation

- India - Australia CECA
- India - Sri Lanka ETCA
- India- Peru FTA
- India - Chile CEPA
- India - USA Bilateral Trade Agreement
- India - Eurasian Economic Union FTA
- India - Korea CEPA — Upgraded negotiations
- ASEAN - India (AITIGA) — Review ongoing

सुविधाजनक चालू खाता घाटे (CAD) की स्थिति

माल व्यापार घाटे की भरपाई सेवाओं के निर्यात और धन प्रेषण' द्वारा की जाती है, जिससे चालू खाता घाटा नियंत्रण में रहता है।

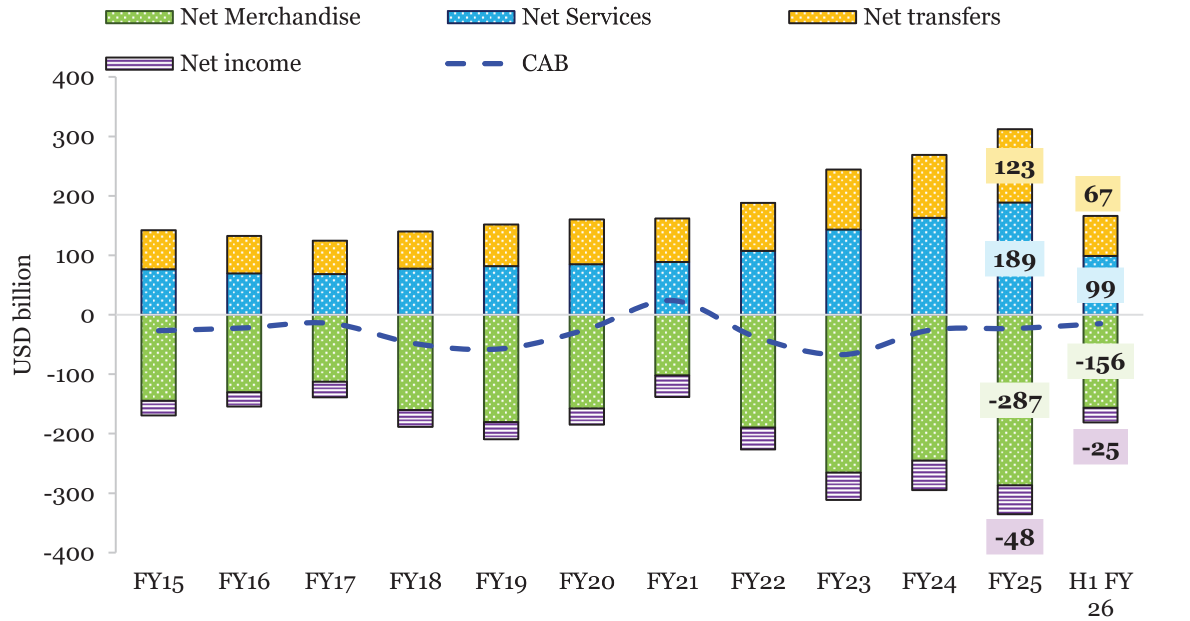

Source: RBI

चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 0.8% रहा, जो वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 1.3% था।

*स्थानांतरण रसीदें मुख्यत: विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा किए गए धन प्रेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं

2020-2024 के बीच भारत हरित क्षेत्रीय डिजिटल निवेश में दुनिया में अग्रणी है

डिजिटल अर्थव्यवस्था में परियोजना घोषणाओं द्वारा शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं में भारत

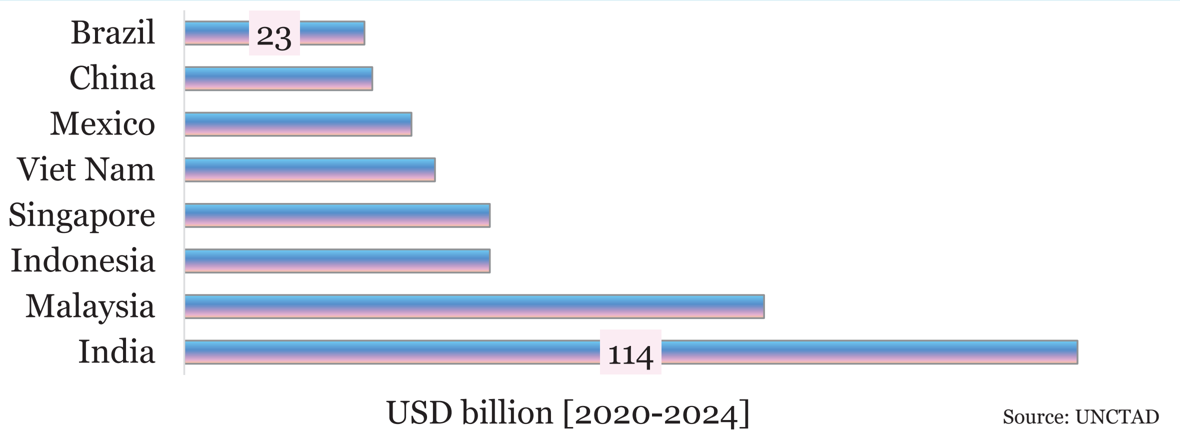

Source: UNCTAD

- भारत हरित क्षेत्र डिजिटल निवेश के लिए सबसे बड़ा गंतव्य बन कर उभरा, जिसने सीवाई 2020-2024 के बीच 114 अरब अमेरिकी डॉलर को आकर्षित किया।
- निवेश डिजिटल सेवाओं, डेटा सेंटर और आईटी अवसंरचना तक फैला हुआ है।

वैश्विक पुनर्निर्देशन को सतत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में बदलना

भारत बड़े पैमाने पर सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करता है

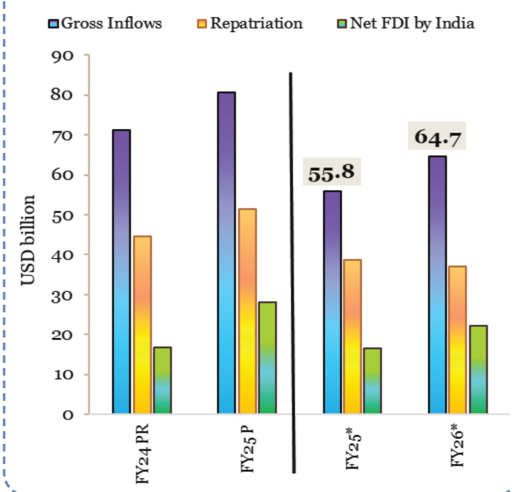

नोट: *(अप्रैल-नवंबर); P: अस्थायी; PR: अस्थायी रूप से संशोधित

अगला कदम निवेश को गहरा करना है

इन कारकों के कारण भारत को पुनर्गठित ग्लोबल वैल्यू चेन (GVCs) से जुड़ने और मूल्य-वृद्धि की सीढ़ी पर चढ़ने का अवसर मिलता है

नोट: जी वी सी : ग्लोबल वैल्यू चेन

मजबूत बाहरी बफर्स स्थिरता को आधार देते हैं (वित्तीय वर्ष 15 बनाम वित्तीय वर्ष 25)

From FY15 → 2025-2026*	
Forex Reserves $341.6 bn in FY15 → $701.4 as of 16 January 2026 **Reserves more than doubled**	**External debt to GDP** 23.8% in FY15 → 19.2% end-Sept 2025 **Lower external leverage**
Import Cover From 8.9 months in FY15 → To 11.1 months as of 9 January 2026 **Stronger import buffer**	**Current Account Deficit/GDP** -1.32% in FY15 → -0.8% in H1 FY26 **Improved external balance**

* As of the latest available data.

भारत 2026 में बाहरी झटकों के खिलाफ मजबूत सुरक्षात्मक उपायों के साथ प्रवेश करता है।

5 मुद्रास्फीतिः नियंत्रित और स्थिर

सीपीआई श्रृंखला की शुरुआत के बाद से भारत में सबसे कम मुद्रास्फीति दर दर्ज की गई, जिसमें अप्रैल-दिसंबर '25 के दौरान औसत शीर्षक मुद्रास्फीति 1.7 % रही; यह मुख्यतः खाद्य मुद्रास्फीति के दबे रहने के कारण संभव हुआ।

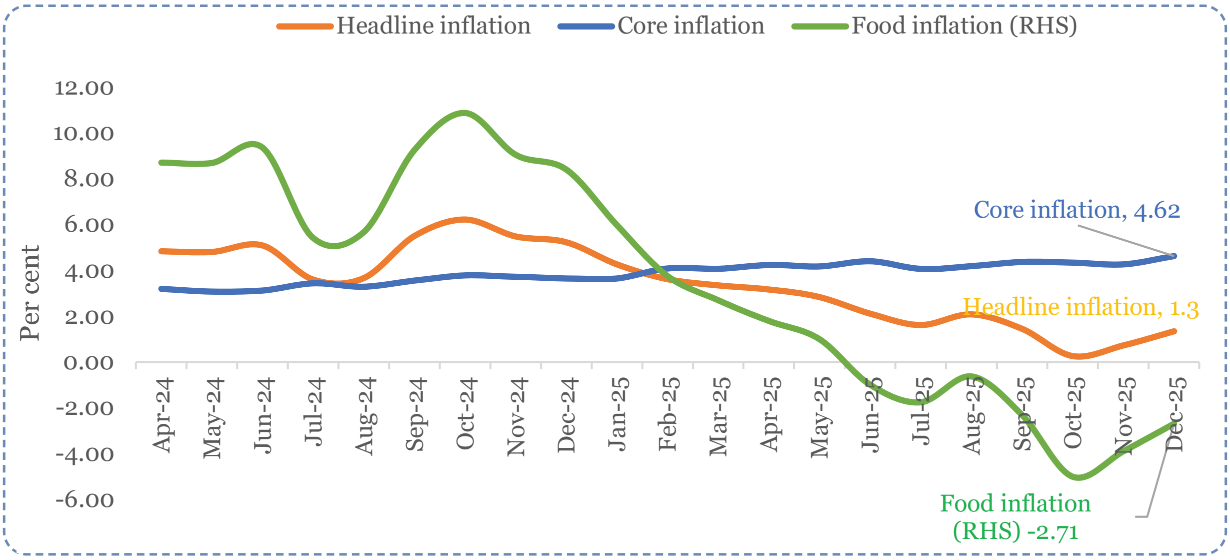

स्रोतः एमओएसपीआई से प्राप्त डेटा के आधार पर गणना की गई।

2025 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत में शीर्षक मुद्रास्फीति में सबसे अधिक (1.8 प्रतिशत) की गिरावट दर्ज की गई है।

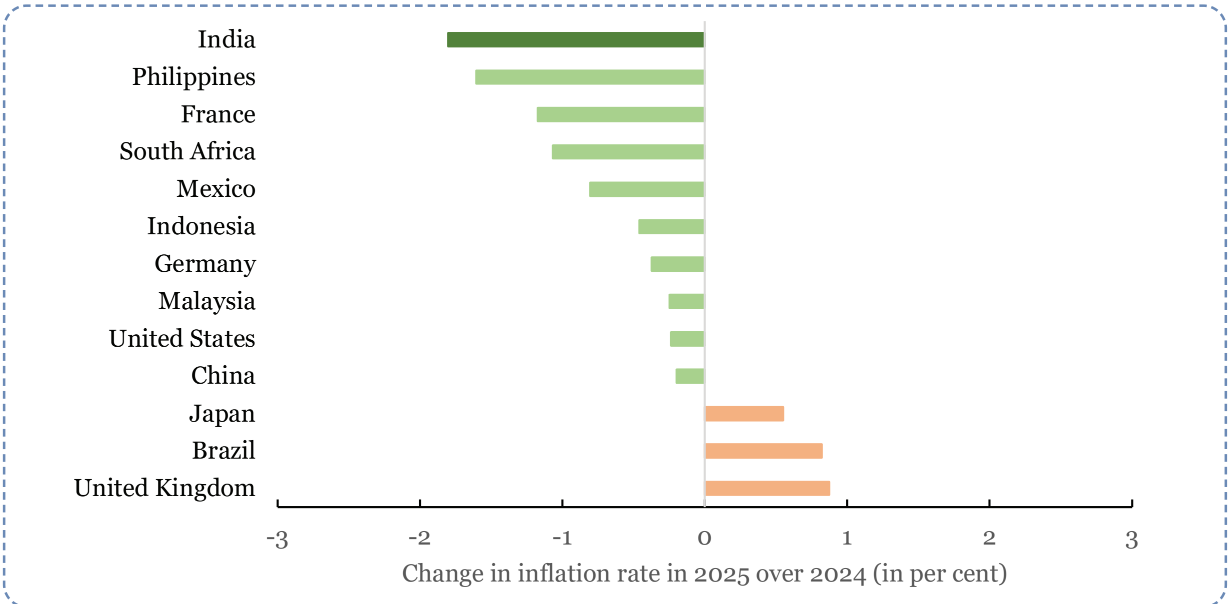

स्रोतः विश्व आर्थिक परिदृश्य डेटाबेस, आईएमएफ

खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट का कारण सब्जियों और दालों जैसी प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में लगातार कमी आना था।

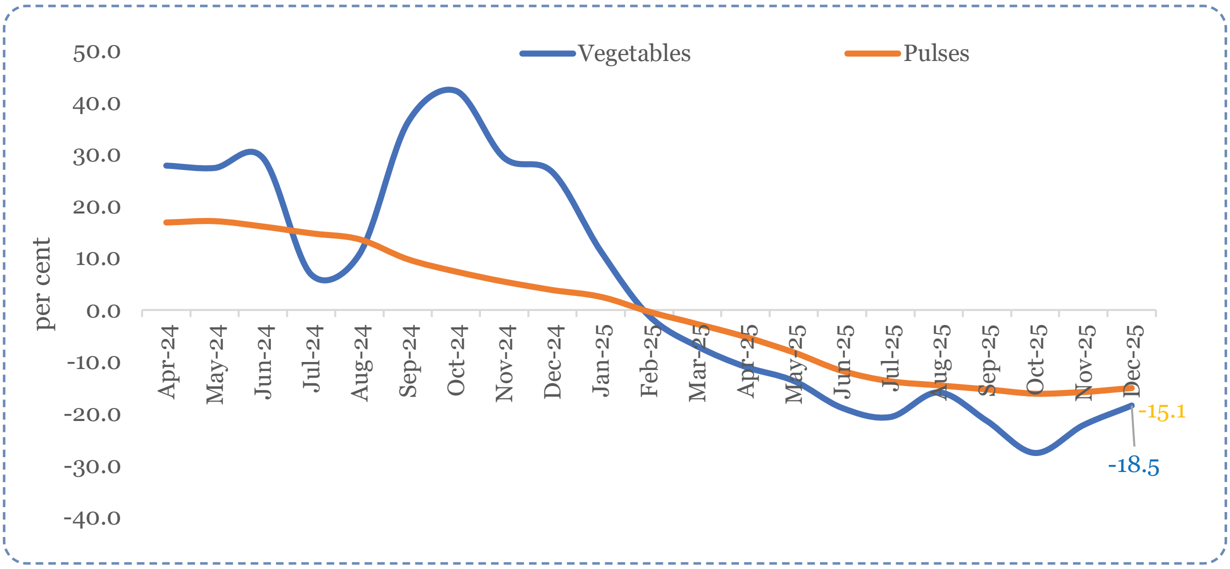

स्रोत: एमओएसपीआई

मजबूत आधार प्रभाव ने विशेष रूप से 2025 की दूसरी छमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

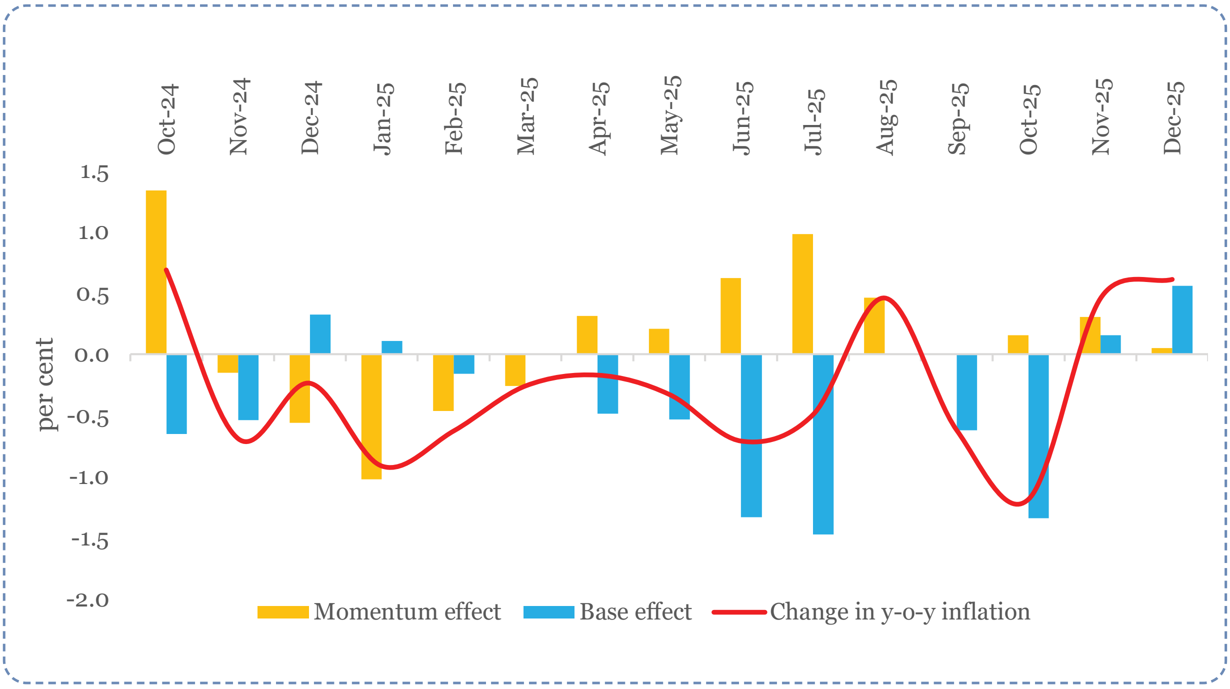

स्रोत: सीपीआई से परिकलित

कोर मुद्रास्फीति की स्थिर गति मुख्यतः सोना और चाँदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में उच्च मुद्रास्फीति से प्रभावित रही है।

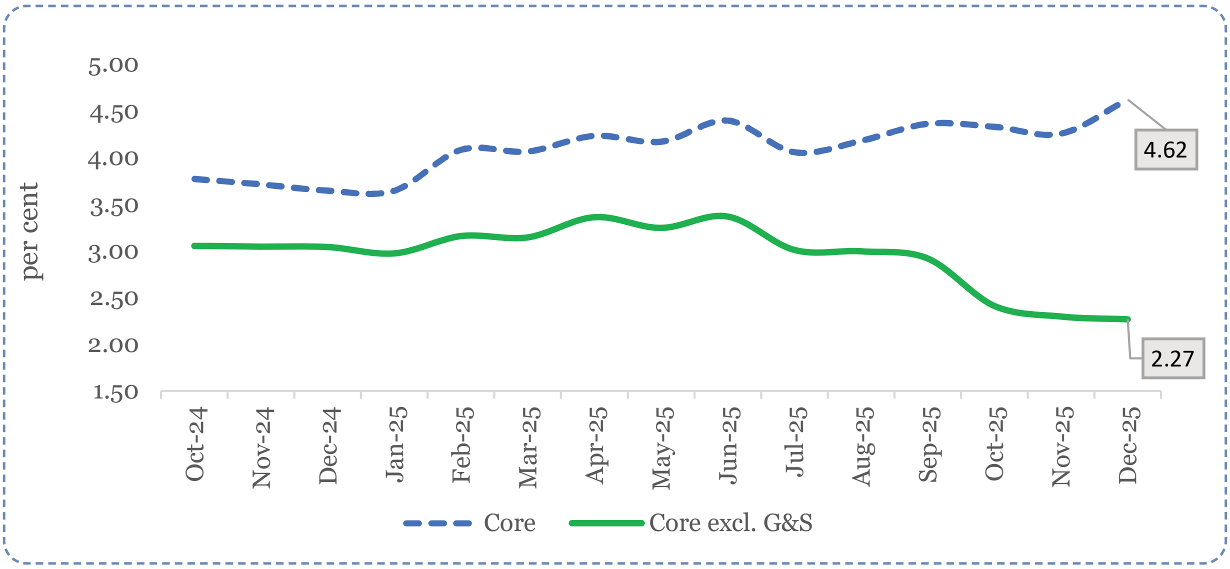

स्रोत: सीपीआई के आंकड़ों से परिकलित

विनिर्माण क्षेत्र की व्यापार शर्तें (टीओटी) कृषि और सेवा जैसे अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्रमिक रूप से कमजोर हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी आई है।

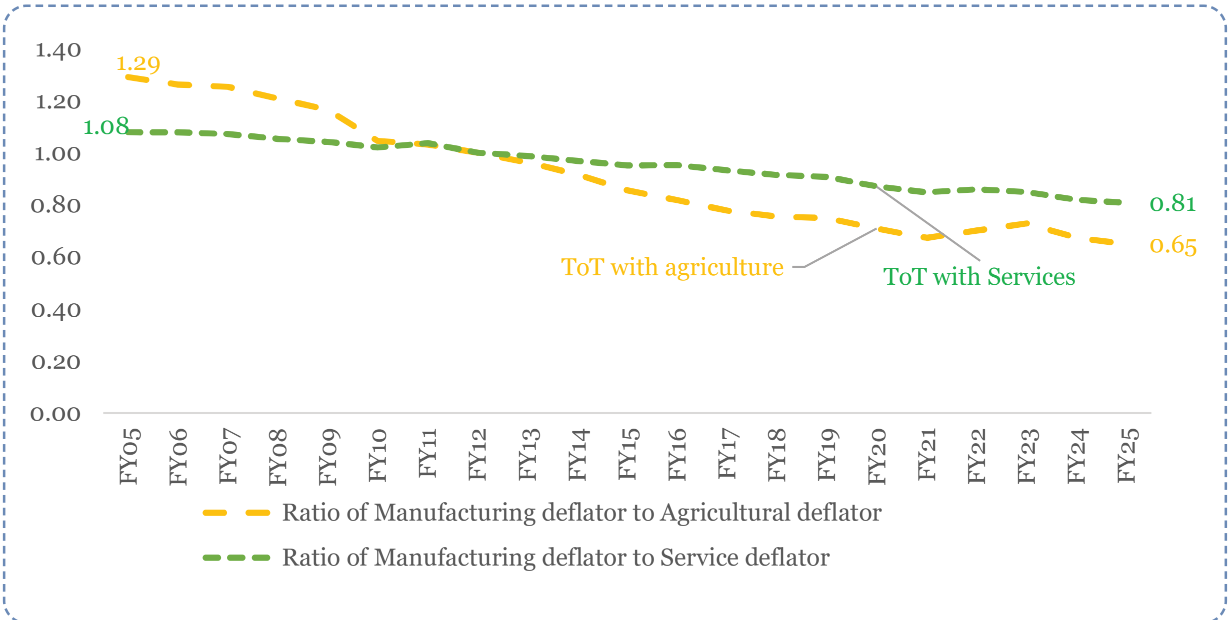

स्रोत: सीपीआई के आंकड़ों से परिकलित।

मुद्रास्फीति को सौम्य बनाए रखने वाले कारक

प्रमुख धातुओं के वैश्विक मूल्यों में मध्यम स्तर की मुद्रास्फीति

सामान्य से कम तापमान तथा सामान्य से अधिक मानसून के संयुक्त प्रभाव से देश में कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई।

खाद्यान्नों की भंडार स्थिति में सुधार

जीएसटी दरों के युक्तिकरण का वस्तुओं की कीमतों में परिलक्षित होना

समय पर हस्तक्षेप से पिछले कुछ वर्षों में दालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव कम करने में मदद मिली।

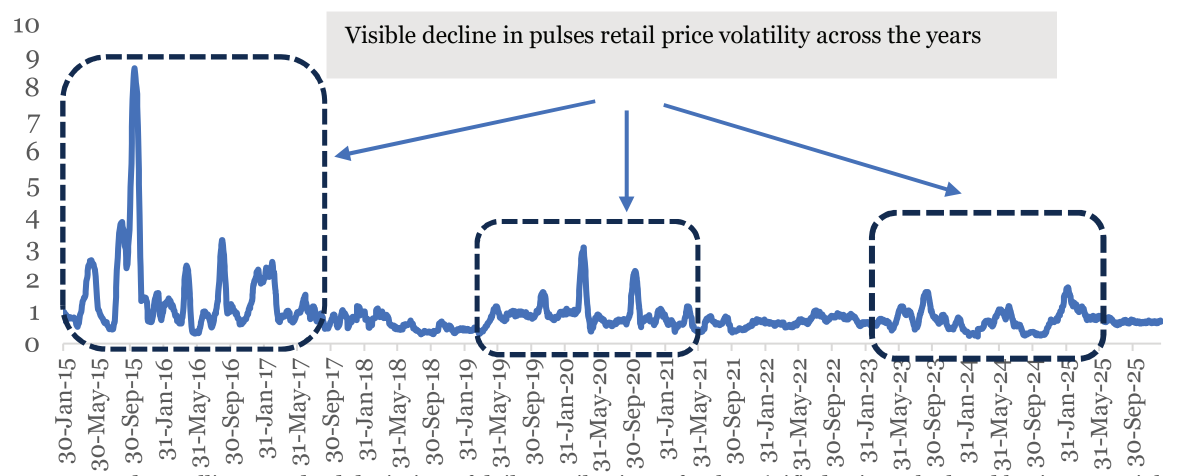

Note: 30-day Rolling standard deviation of daily retail prices of pulses (uified price calculated basis CPI weight from Jan.2015 to 11 Jan. 2026.

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दैनिक डेटा से परिकलित।

6 कृषि और खाद्य प्रबंधन: उत्पादकता वृद्धि, आय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

उत्पादकता बढ़ाना, आय सुरक्षित करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

कृषि का विविधीकरण: पशुपालन और मत्स्य पालन अग्रणी

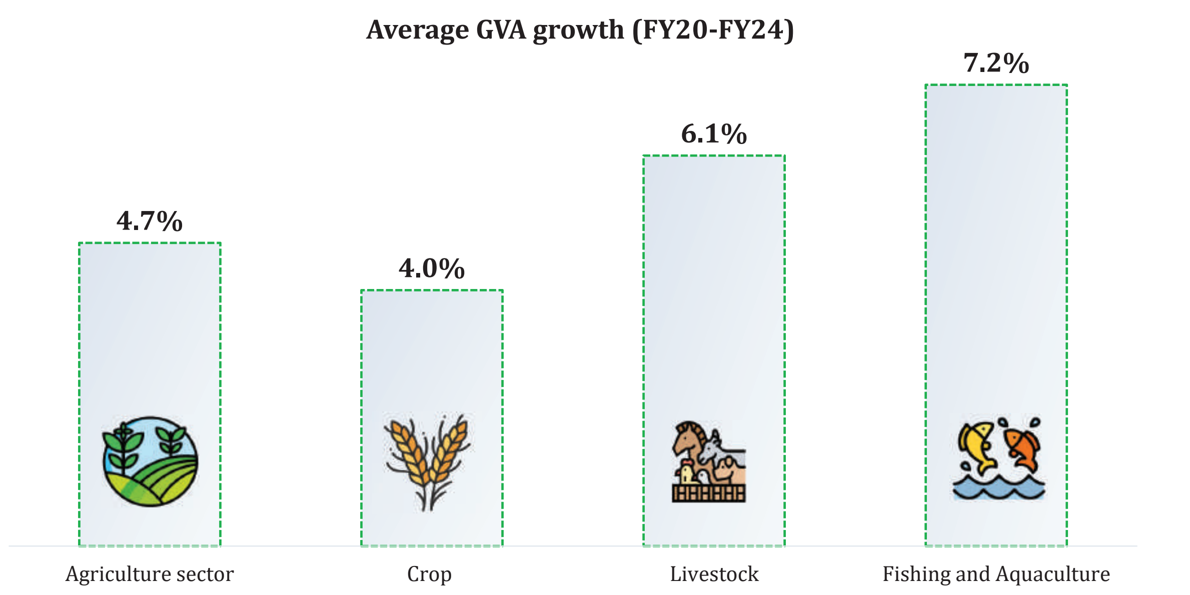

नीतिगत विचार

इथेनॉल मूल्य निर्धारण और फसल प्रोत्साहन

- फसलों में अनपेक्षित एकाग्रता से बचने के लिए प्रोत्साहनों का सावधानीपूर्वक समायोजन आवश्यक है।
- एथेनॉल के विस्तार को इस प्रकार आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दोनों का समर्थन करे।

कृषि संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप उर्वरकों का उपयोग करना

- उर्वरक संबंधी निर्णय मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दोनों का समर्थन करे।

फसल विविधीकरण के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण प्रोत्साहन

- फसलों का चयन स्थानीय मिट्टी, वर्षा और बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिससे आर्थिक और कृषि संबंधी व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।
- प्रति एकड़/प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि से संक्रमणकालीन नुकसान की भरपाई होती है; कम इनपुट लागत से लाभ में सुधार होता है।

किसानों को सरकारी सहायता

नीति और संस्थागत सहायता

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन
- खाद्य तेल-तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन
- खाद्य तेल-ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन
- कृषि विज्ञान केंद्र
- एफपीओ और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
- पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से बीमा सहायता
- कृषोन्नति योजना
- डिजिटल कृषि मिशन

इनपुट समर्थन

- उच्च उपज वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सुनिश्चित सिंचाई
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- उर्वरक सब्सिडी
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना
- पशुधन के लिए खाद्य एवं मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- मत्स्य पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना

आय सहायता

- पीएम किसान
- न्यूनतम समर्थन मूल्य
- पीएम मानधन योजना

7 सेवाएँ: स्थिरता से नए आयामों तक

लचीला और स्थिर: भारत की सर्विसेज जीवीए ग्रोथ ग्लोबल ट्रेंड्स से बेहतर है

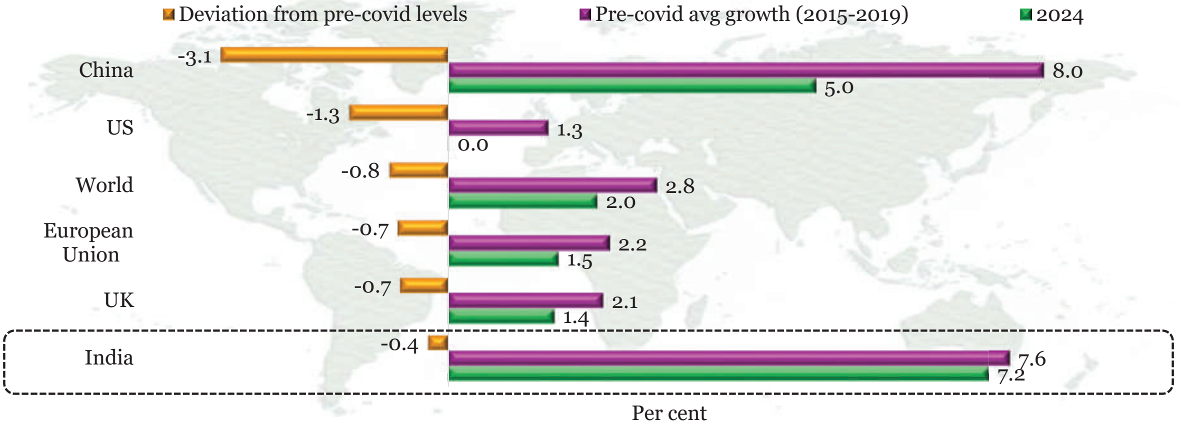

सर्विस सेक्टर ग्रोथ का मुख्य कारक बना हुआ है

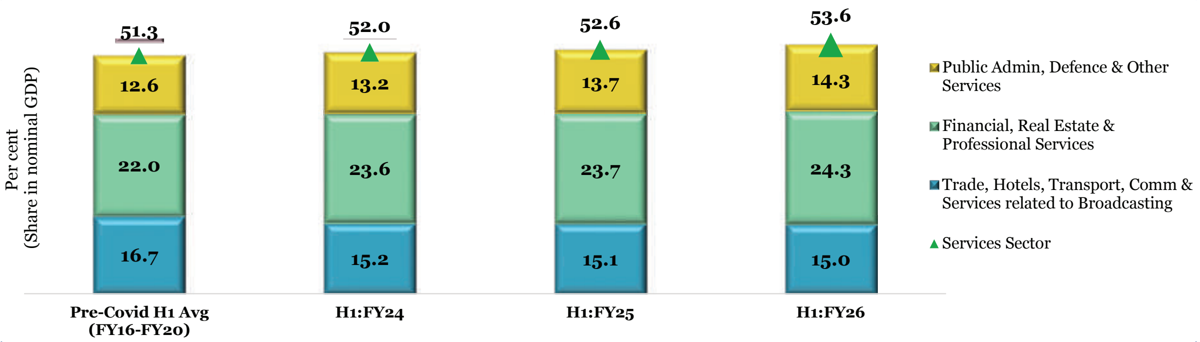

वित वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में सेवा पीएमआई दीर्घावधि औसत से अधिक बढ़ा

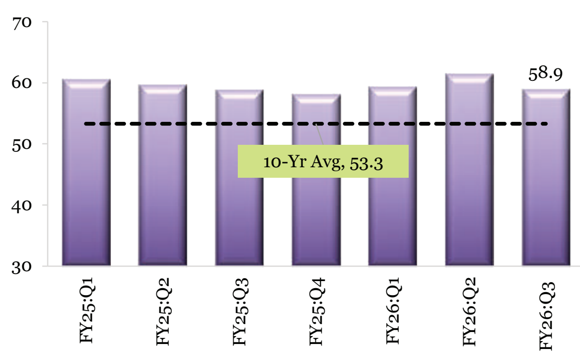

सेवा क्षेत्र शहरी रोजगार को बढ़ाता है

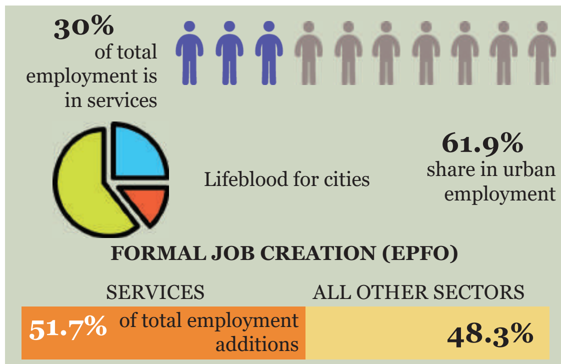

हाई-वैल्यू सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल सर्विसेज की वजह से सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ा है।

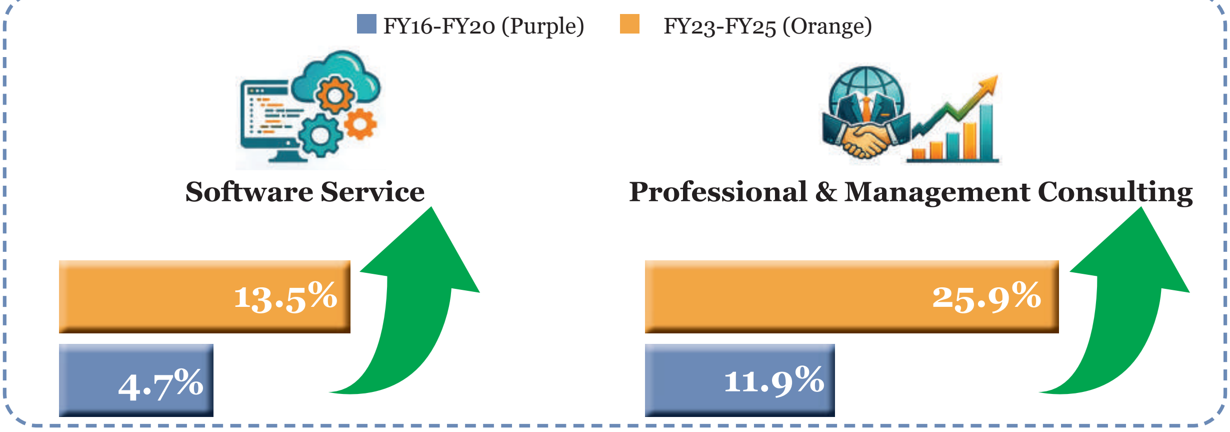

ट्रांसपोर्ट सर्विस: कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस को मजबूत करना

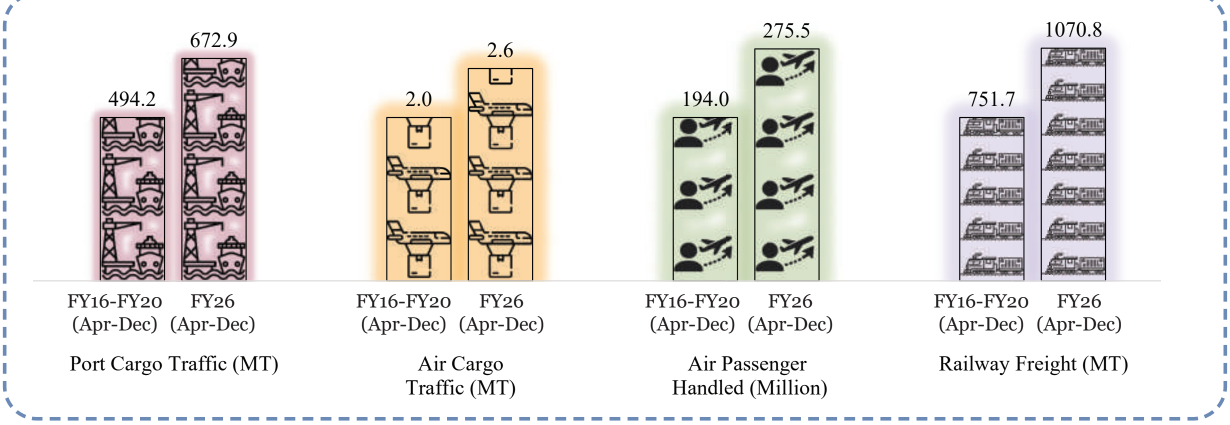

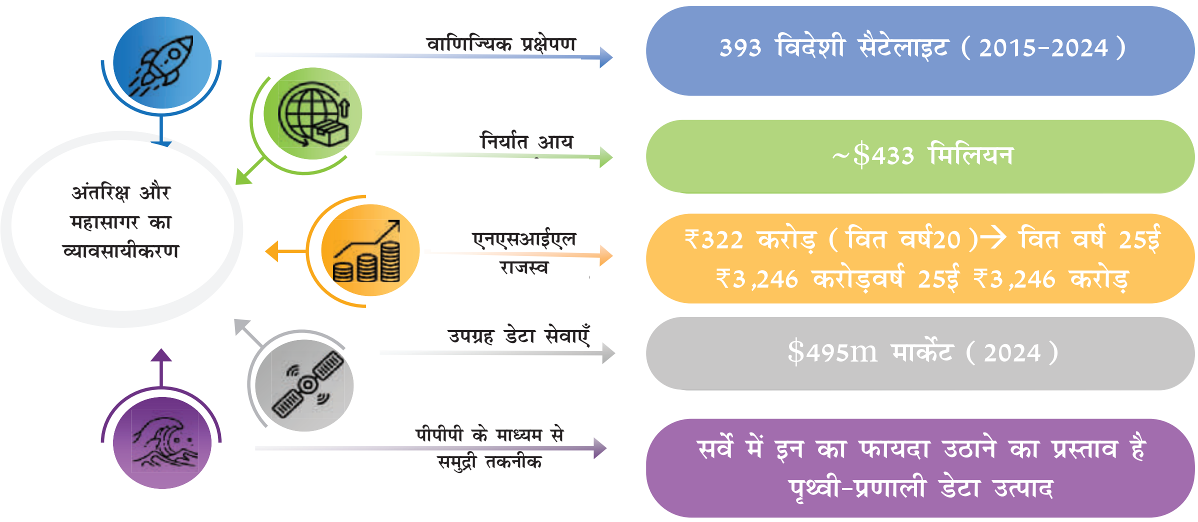

टूरिज्म सेक्टर: उभरते हाई-वैल्यू सेगमेंट के साथ घरेलू लचीलापन

- घरेलू पर्यटक यात्राओं में 17.5% वृद्धि (2024)
- अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 8.9% वृद्धि (2024)
- >60% औसत होटल अधिभोग दर (वित्तीय वर्ष 2024-2026)

चिकित्सा एवं कल्याण पर्यटन	अराइवल सीएजीआर: 2009-2024 के दौरान 12%
लंबी दूरी के ट्रेल्स का प्रस्ताव	दूर-दराज के इलाकों में टूरिज्म के जरिए रोजी-रोटी बढ़ाने के लिए
मरीना पर्यटन/नीली अर्थव्यवस्था	मरीना डेवलपमेंट पॉलिसी, हाई-वैल्यू कोस्टल टूरिज्म, कोस्टल जॉब्स और इनकम, पोर्ट रिवाइटलाइज़ेशन

मीडिया एवं मनोरंजन

- सेक्टर का साइज ~ 2.5 ट्रिलियन (2024). डिजिटल मीडिया = मुख्य ग्रोथ इंजन (~कुल रेवेन्यू का एक-तिहाई)
- गेमिंग से रेवेन्यू ~ 232 बिलियन, एनिमेशन और VFX से ~ 103 बिलियन, 2024 में
- ऑरेंज इकॉनमी: लाइव एंटरटेनमेंट > 100 बिलियन (2024); टूरिज्म और शहरी सेवाओं पर इसका अच्छा असर

रियल एस्टेट एवं आवास सेवाएँ : सतत उर्ध्वचक्र

तिमाही औसत आवास बिक्री सेवाएँ : सतत उर्ध्वचक्र

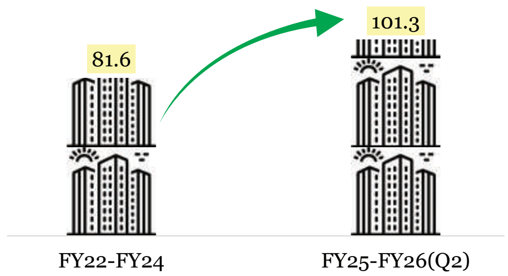

आईटी क्षेत्र-वैश्विक प्रौद्योगिकी एवं नवाचार केंद्र

वैश्विक क्षमता केंद्रों का सतत विस्तार

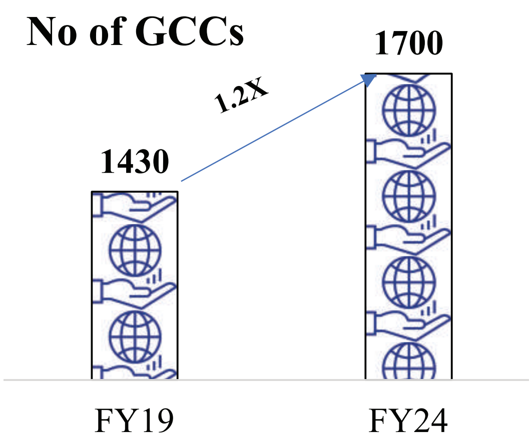

भारत का प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पारितंत्र विश्व में तीसरा सबसे बड़ा

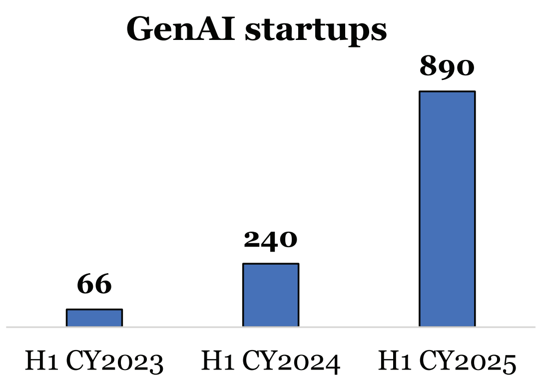

8 उद्योग का अगला चरण: संरचनात्मक परिवर्तन और वैश्विक एकीकरण

उद्योग का प्रदर्शन: विकास, लचीलापन और परिवर्तन

भविष्य की संभावनाओं को लेकर आशावाद अभी भी उच्च बना हुआ है।

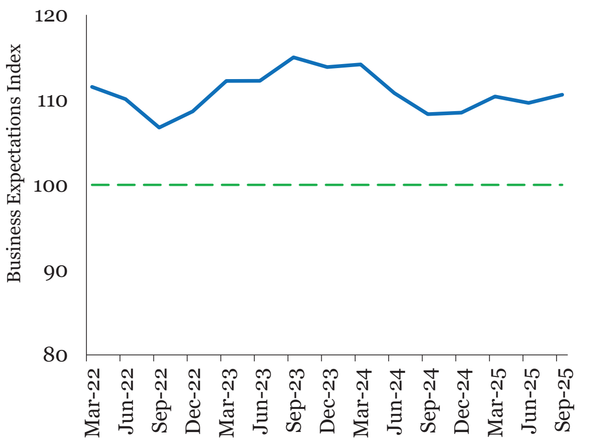

स्रोत: व्यावसायिक अपेक्षा सूचकांक (बीईआई) (आरबीआई औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का सर्वेक्षण: दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 2026)। नोट: बीईआई झ100 – आशावाद; बीईआई ढ100 – निराशावाद।

भारत के कुल विनिर्माण मूल्यवर्धन में मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों का योगदान अब 46.3 प्रतिशत है।

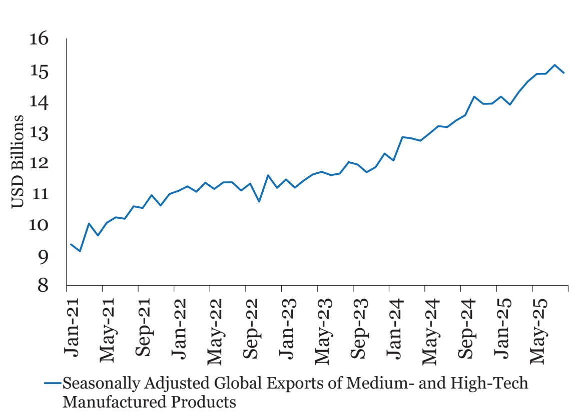

स्रोत: यूएनआईडीओ सांख्यिकी

वास्तविक विनिर्माण सकल मूल्य वृद्धि में निरंतर गति (वर्ष-दर-वर्ष)

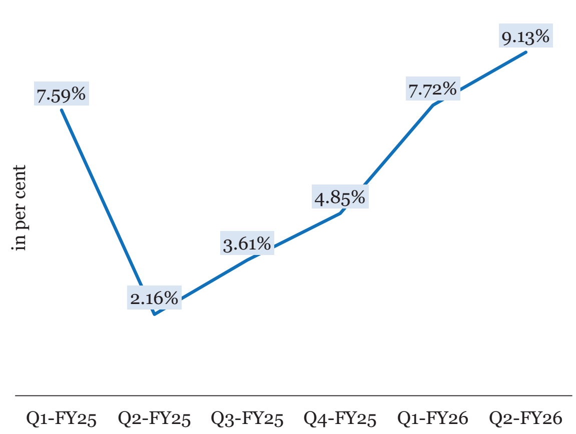

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, एमओएसपीआई

वास्तविक उद्योग सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

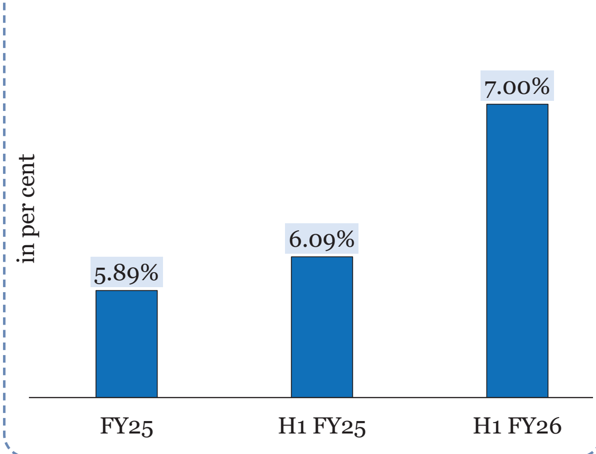

टिप्पणी : उद्योग में चार उप-क्षेत्र शामिल हैं – विनिर्माण; बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं; निर्माण और खनन एवं उत्खनन।
स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, एमओएसपीआई

सीमेंट: स्थापित क्षमता और उत्पादन में वृद्धि

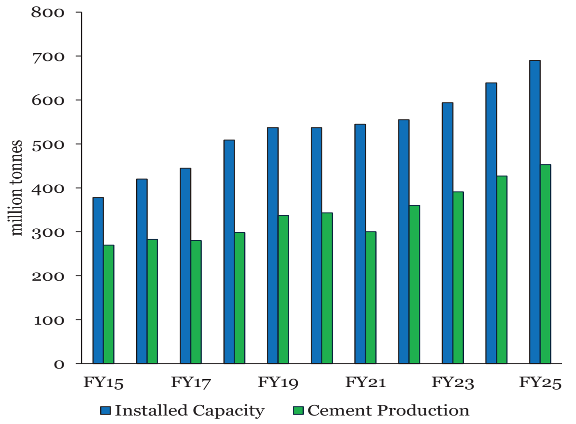

स्रोत: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)

तैयार इस्पात: उत्पादन और खपत में वृद्धि

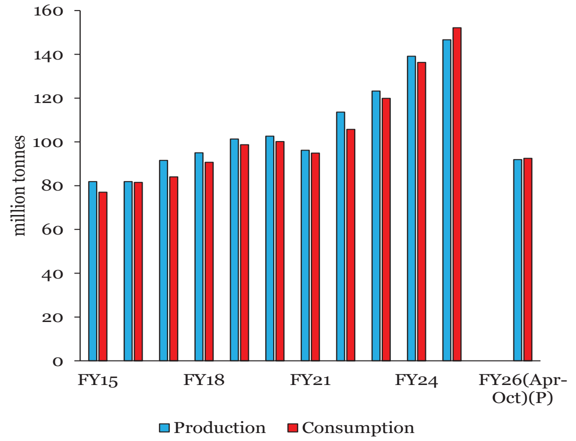

स्रोत: इस्पात मंत्रालय

कोयला: घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में कमी

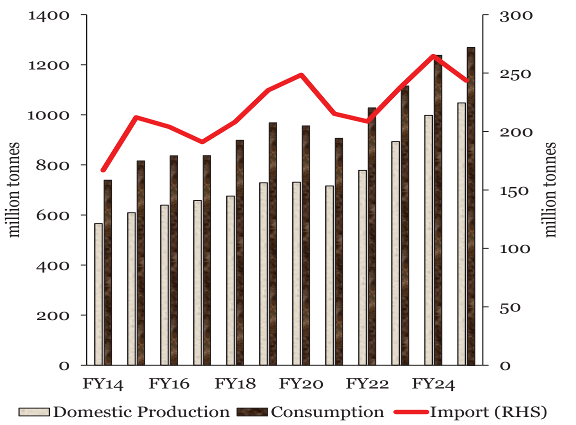

स्रोत: कोयला मंत्रालय।

फार्मास्युटिकल उद्योग के निर्यात में वृद्धि

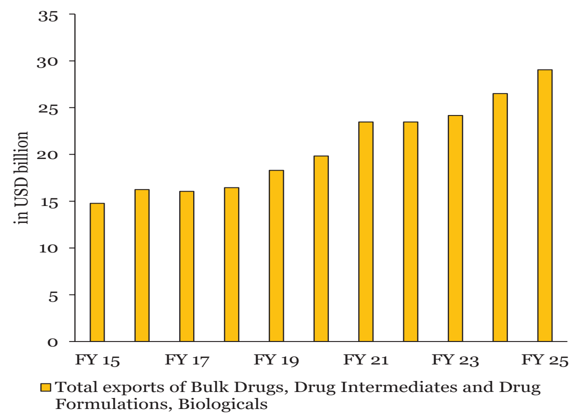

स्रोत: वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

ऑटोमोबाइल का उत्पादन, बिक्री और निर्यात

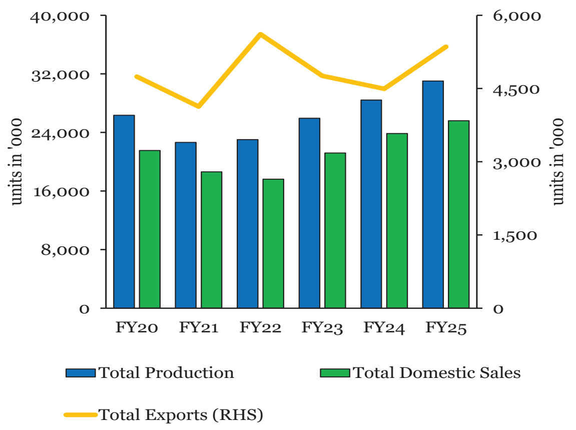

स्रोत: एसआईएम; भारी उद्योग मंत्रालय।

ईवी पंजीकरण बढ़ रहा है

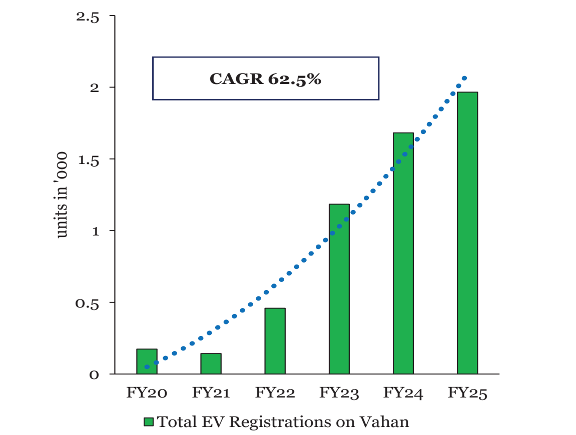

स्रोत: एसआईएम; भारी उद्योग मंत्रालय।

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और निर्यात में वृद्धि

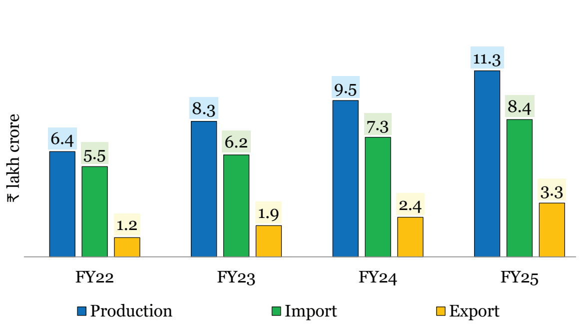

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मोबाइल विनिर्माण उत्पादन मूल्य में लगभग 30 गुना वृद्धि

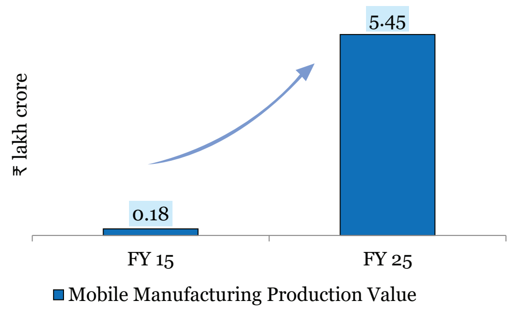

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र: अनुसंधान, बौद्धिक संपदा और उद्यमशीलता

वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है।

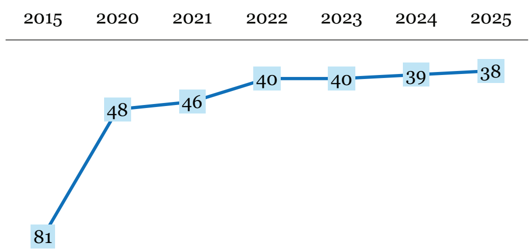

स्रोत: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में तीव्र वृद्धि

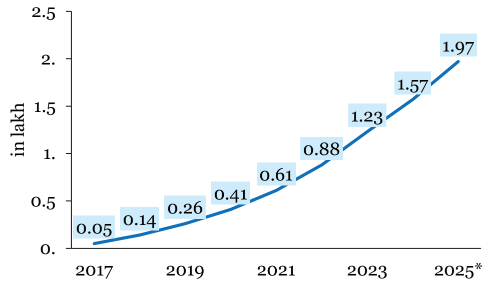

स्रोत: डीपीआईआईटी. नोट: *वर्ष 2025 का डेटा 31 अक्टूबर 2025 तक का है।

वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 तक पेटेंट आवेदनों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।

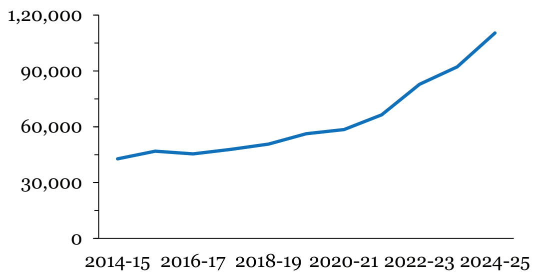

स्रोत: डीपीआईआईटी

वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 तक ट्रेडमार्क पंजीकरण में 1.5 गुना वृद्धि हुई।

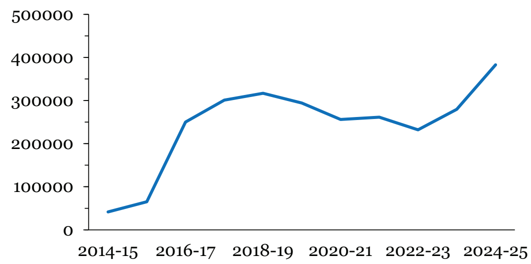

स्रोत: डीपीआईआईटी

वैश्विक नवाचार में छलांग:

वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान है।

- उद्यमशीलता नीति एवं संस्कृति में बारहवाँ स्थान
- ट्रेडमार्क में चौथा स्थान
- पेटेंट में छठा स्थान
- वैश्विक स्तर पर औद्योगिक डिजाइन में सातवां स्थान

महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता:

- 64 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में से 45 में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में शामिल (2003-07 में 4 से ऊपर)

(ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान)

9 निवेश और अवसंरचना: कनेक्टीविटी, क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता का सुदृढ़ीकरण

वित वर्ष15 से प्रभावी पूंजीगत व्यय में लगातार बढ़ोतरी

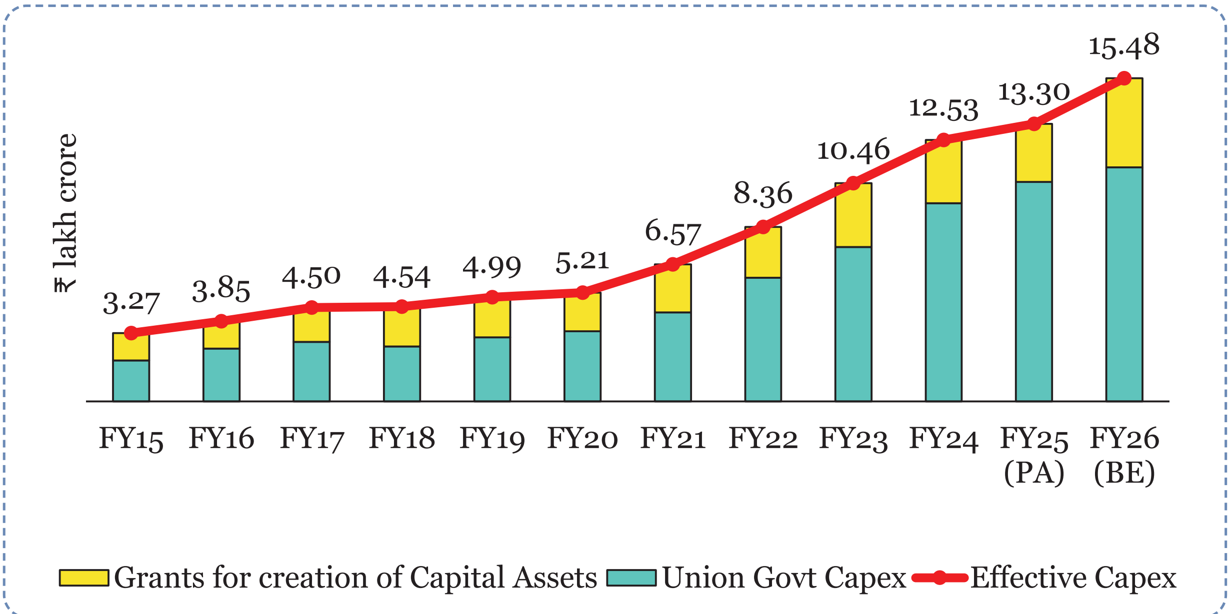

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना अनुमोदनों में वृद्धि

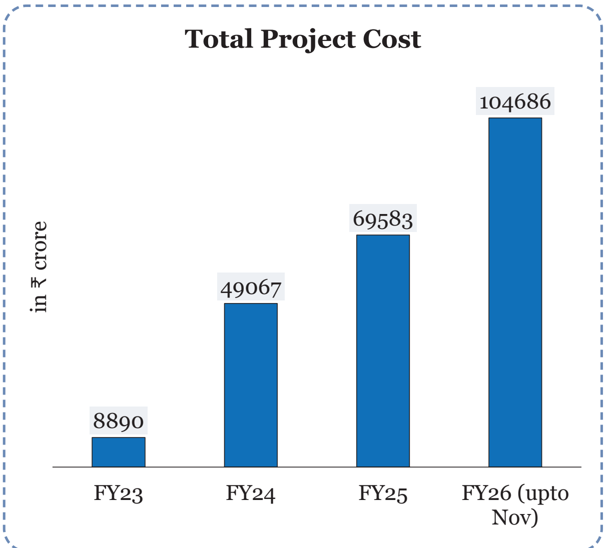

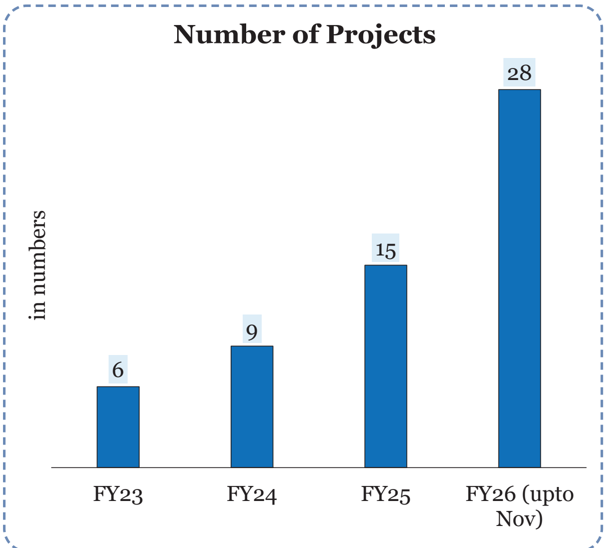

स्रोत: पीपीपी डेटाबेस, आर्थिक कार्य विभाग

भौतिक संपर्क व्यवस्था में सुधार

कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क (60 प्रतिशत वृद्धि)

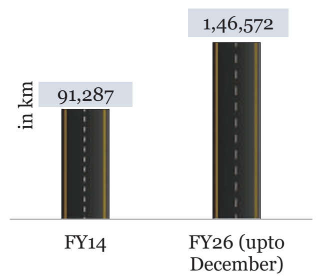

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

संचालित उच्च-गति कॉरिडोर (~10 गुना वृद्धि)

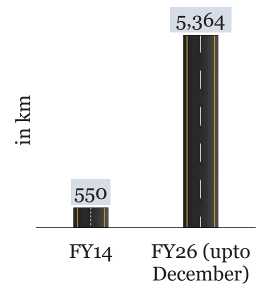

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

वार्षिक औसत रेलवे नेटवर्क कमीशनिंग

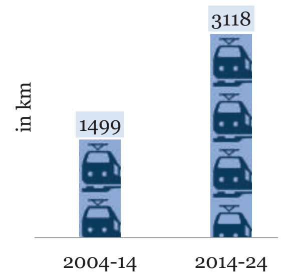

स्रोत: रेल मंत्रालय

बंदरगाह अवसंरचना का विस्तार और रिकॉर्ड माल ढुलाई निष्पादन

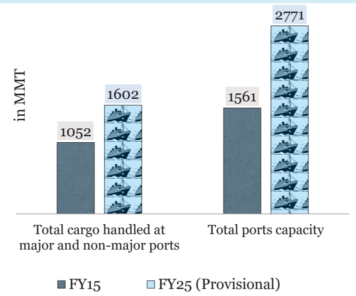

औसत कंटेनर जहाज टर्नअराउंड समय में कमी

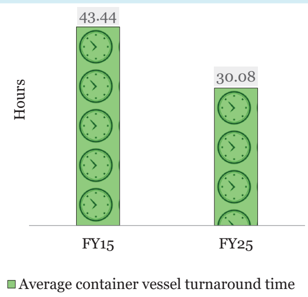

आंतरिक जलमार्ग परिवहन के माध्यम से माल का संचालन

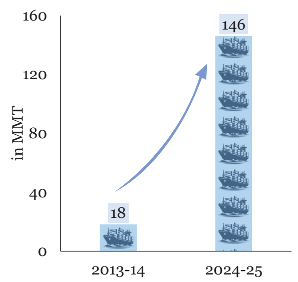

पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

ऊर्जा क्षेत्र

ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता वृद्धि

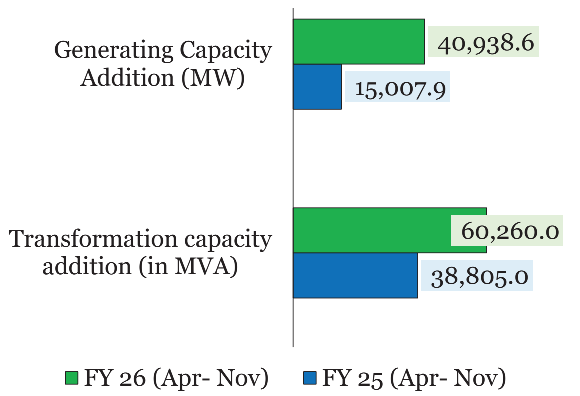

स्रोत: कार्यकारी सारांश रिपोर्ट (नवंबर 2025), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

दैनिक औसत विद्युत आपूर्ति में सुधार

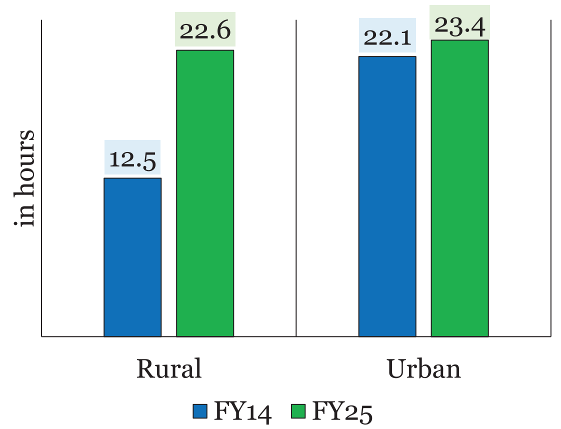

स्रोत: विद्युत मंत्रालय

विद्युत वितरण में सुधार

कर के बाद लाभ: 67,962 करोड़ हानि (वित वर्ष14)→2,701 करोड़ लाभ (वित वर्ष25)

एटी-सी हानि: 22.62% (वित वर्ष14)→15.04% (वित वर्ष25)

डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार

दूरसंचार अवसंरचना में प्रगति (भारत नेट प्रगति)

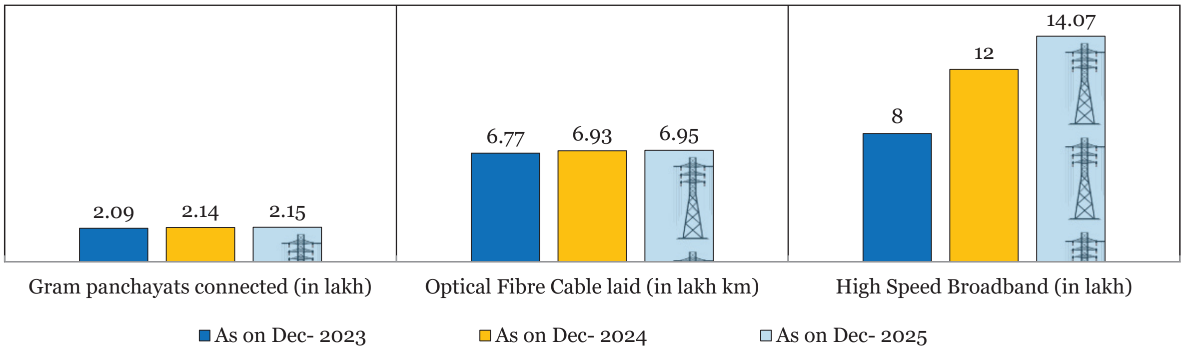

स्रोत: डिजिटल भारत निधि डैशबोर्ड, दूरसंचार विभाग।

दूरसंचार पहुँच का विस्तार

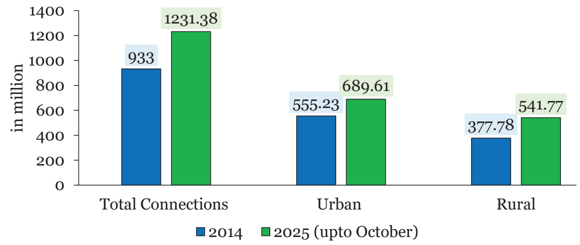

स्रोत: दूरसंचार विभाग।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार

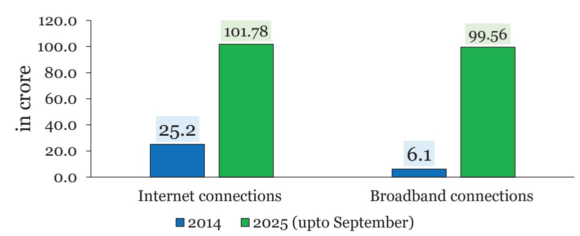

स्रोत: दूरसंचार विभाग।

सुलभता के कारण मासिक डेटा खपत में वृद्धि

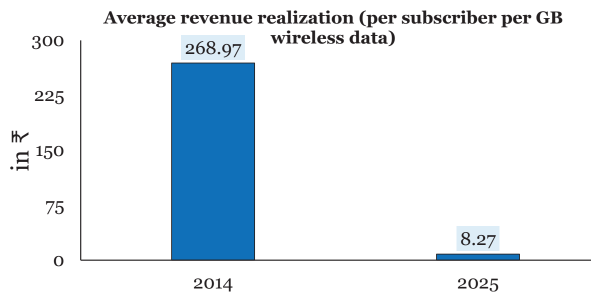

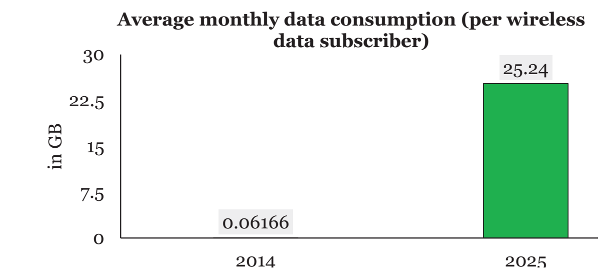

स्रोत: दूरसंचार विभाग। नोट: 2025 के लिए डेटा सितंबर 2025 तक का है।

आज 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल के पानी की सुविधा उपलब्ध है

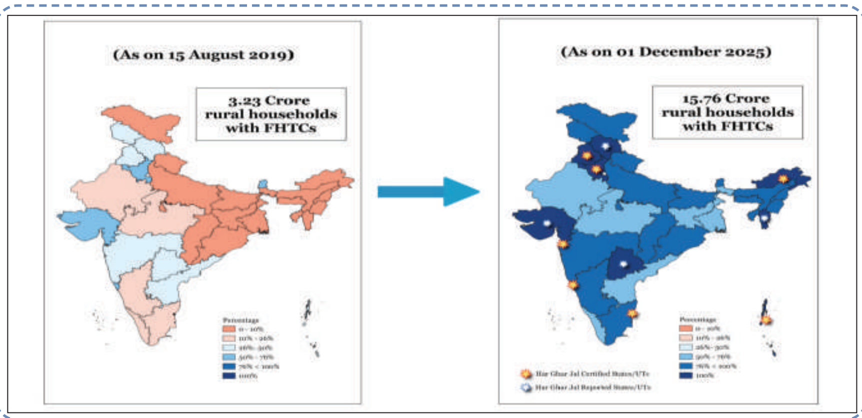

स्रोत: जल जीवन मिशन डैशबोर्ड।

10 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तनः एक प्रतिरोधी, प्रतिस्पर्धी और विकास-संचालित भारत का निर्माण

नवीकरणीय ऊर्जा की संसाधन-गहन चुनौती

सौर ऊर्जा प्रति गीगावाट

आवश्यक सामग्री

रजत ~ 18.5 t
पॉलीसिलिकॉन ~ 2-3 हजार टन
एल्यूमिनियम ~ 10,252t

अपेक्षित ऊर्जा

रजतः 4,625 MWh
~350-400 परिवार/वर्ष
एल्यूमिनियमः 1,948,000 GJ

पवन ऊर्जा प्रति गीगावाट

आवश्यक सामग्री

तांबाः 2,866 टन 0.6
प्रतिशत प्राप्ति के साथ कुल सामग्री
= 477,666.6t

ट्रकलोड

~1,194 ट्रक लोड (400 टन ट्रक)

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना मूल रूप से सामग्री, खनन और ऊर्जा से संबंधित चुनौती है।

नाभिकीय ऊर्जा: भारत स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा संक्रमण का स्तंभ

नाभिकीय ऊर्जा क्यों ?

24/7 स्वच्छ ऊर्जा
कार्बन-मुक्त ऊर्जा

रुकावट रहित ऊर्जा
ऊर्जा सुरक्षा

भारी उद्योग को समर्थन

विश्वसनीय बेसलोड
टेक-रेडी पावर

हाइड्रोजन उत्पादन

परिवहन ईंधन
औद्योगिक उपयोग

राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन (2025-26)

केंद्रीय बजट 2025-26 में ₹20,000 करोड़ का आवंटन

- 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएम आर का विकास
- **लक्ष्य:** 2033 **तक परिचालन**
- **ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान**

8,780 मेगावाट वर्तमान परमाणु क्षमता	→	**2047 तक 100 गीगावाट** लक्षित क्षमता

शांति अधिनियम - दिसंबर 2025

- निजी और राज्य की भागीदारी को सक्षम बनाता है
- सांकेतिक दायित्व फ्रेमवर्क
- पीड़ित मुआवजे की सुरक्षा करता है
- निर्माण, अनुसंधान और विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देता है

भारत की ऊर्जा भंडारण आवश्यकता और नीतिगत प्रयास

ऊर्जा भंडारण को नवीकरणीय एकीकरण, उच्चतम मांग प्रबंधन और दीर्घकालिक संसाधन पर्याप्तता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्थित किया गया है।

अपेक्षा **भारत को** 2031-32 तक लगभग 411 गीगावाट घंटे ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होगी

नीति समर्थन

ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ढांचा	बिजली नियमों के अंतर्गत औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त	सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में अवसंरचना शामिल	'संसाधन योग्यता योजनाओं' के तहत पावर सिस्टम योजना में एक मुख्य संसाधन।

बाजार समर्थक और तैनाती सहायता

अंतर-राज्य संचरण प्रणाली शुल्क की छूट	भंडारण संपत्ति को सहायक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है	उत्पादन सम्बंधित प्रोत्साहन योजना- 50 GWhour एसीसी निर्माण के लिए ₹18,100 करोड़	(VGF) योजनाएँ, जो लगभग 43 गिगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) को लक्षित करती हैं

हाल ही में पर्यावरण नियमों में सुधार

परिवेश 3.0 - एकल विंडो मंज़ूरी

डिजिटल अनुमोदन और मंज़ूरी के बाद की निगरानी

देशव्यापी समान दिशानिर्देश

जल और वायु संबंधित कानूनों में संशोधनों के माध्यम से स्थापित/संचालन के लिए सहमति

सरलीकृत खनन नियम

महत्वपूर्ण, रणनीतिक और परमाणु खनिज

तृतीय-पक्ष पर्यावरणीय लेखा परीक्षा

पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025

अद्यतनित ग्रेडेड उद्योग वर्गीकरण

बेहतर अनुपालन को बढ़ावा दें

सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना

सर्कुलर इकोनॉमी कार्रवाई योजनाएं जो 10 अपशिष्ट श्रेणियों को शामिल करती हैं, कई अपशिष्ट धाराओं के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) फ्रेमवर्क, एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से गैर-आपराधिक बनाना

जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से अपराध की श्रेणी से बाहर करना

उद्योगों के लिए 'ग्रीन बेल्ट' आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित किया गया

औद्योगिक परिसरों/उद्यानों और व्यक्तिगत उद्योगों की प्रदूषण संभावना के आधार पर

भारत के जलवायु और संधारणीय वित्त ढांचे में प्रमुख मील के पत्थर

2017

'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड' द्वारा ग्रीन बॉन्ड के जारी करने और सूचीबद्धता के लिए प्रकटी. करण मानदंड

2021

सेबी द्वारा बीआरएसआर: शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यवसाय जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टिंग: वित्तीय वर्ष 22 के लिए स्वैच्छिक, वित्तीय वर्ष 23 से अनिवार्य

2022

वित्त मंत्रालय द्वारा संप्रभु ग्रीन बॉन्ड्स के लिए ढांचा

'इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेस सेंटर अथॉरिटी' द्वारा सतत और स्थायित्व-संबंधी लिंक्ड लेंडिंग पर मार्गदर्शन।

2023

सेबी द्वारा प्रस्तुत बीआ. रएसआर कोर : मुख्य ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेस) संकेतकों के लिए आश्वासन-आधारित रिपोर्टिंग; ग्रीनवॉशिंग को कम करने और स्थिरता डेटा की विश्वसनीयता में सुधार लाने हेतु मूल्य-श्रृंखला प्रकटीकरण(वैल्यू-चेन डिस्क्लोजर) की शुरुआत की गई है।

भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग: मूल्य श्रृंखला के लिए प्रमुख पर्यावरणीय

2025

व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बीआरएसआर कोर में आशोधन; जिसमें आश्वासन या मूल्यांकन के ढांचे, मूल्य श्रृंखला के लिए ईएसजी प्रकटीकरण और 'ग्रीन क्रेडिट' पर स्वैच्छिक प्रकटीकरण की शुरुआत शामिल है।

व्यवसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टिंग (BRSR) में संशोधन व्यापार करने में आसानी को सुनिश्चित करने के लिए मूल रूप से फ्रेमवर्क के तहत आश्वासन या मूल्यांकन, मूल्य श्रृंखला के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी प्रकटी. करण, और ग्रीन क्रेडिट पर स्वैच्छिक प्रकटीकरण की शुरुआत की गई है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्रवाई योजनाओं का विकास

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्रवाई योजनाएँ (2010-15)
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना के साथ व्यापक सरेखण, मिशन मुख्य रूप से उत्सर्जन कम करने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित, स्वतंत्र जलवायु परियोजनाएँ, सीमित बजट।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (2020 से आगे)

अनुकूलन-आधारित विकास दृष्टिकोण

राज्य एवं जिला-विशेष जलवायु जोखिम विश्लेषण

योजना और वित्त विभागों के साथ समाकलन

मुख्य सामाजिक क्षेत्र योजनाओं (जल, कृषि, शहरी) के साथ समन्वय

समुदायों और स्थानीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका

परिणाम- और लचीलापन-केंद्रित निगरानी।

11 शिक्षा और स्वास्थ्य: उपलब्धियां और भविष्य की रूपरेखा

भारत का शिक्षा परिदृश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की प्रमुख उपलब्धियाँ

सार्वभौमिक पहुँच

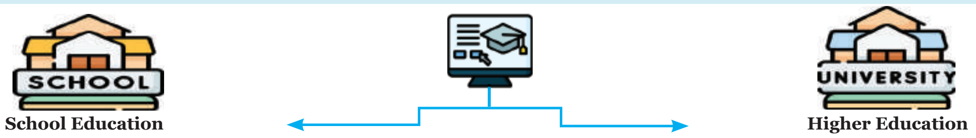

स्कूली शिक्षा 2030 तक 100% जीईआर प्राप्त करना

- 14.7 लाख विद्यालयों में 25 करोड़ के करीब विद्यार्थी नामांकित हैं, जिन्हें 1 करोड़ से अधिक शिक्षक सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- जीईआर' :कक्षा I से V →90.9,कक्षा VI से VIII →90.3,कक्षा IX और X →78.7, कक्षा XI और XII →58.4(स्रोत: यूडीआईएसई+)

उच्च शिक्षा 2035 तक 50 प्रतिशत जीईआर प्राप्त करना

- देशभर में 70,018 से अधिक संस्थानों में 4.46 करोड़ विद्यार्थी नामांकित हैं।
- जीईआर 2019-20 में 27.1 से बढ़कर 2022-23 में 29.5 हो गया (एआईएसएचई)।

समावेशिता एवं समानता

- पीएम-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के अंतर्गत 500 छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की गई।
- 2,682 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन किया गया।
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 692 छात्रावासों को स्वीकृति दी गई।

बहुभाषिकता

- बहुभाषी स्वरूप में 3,000 से अधिक एआई-संचालित इंटरैक्टिव ई-सामग्री उपलब्ध कराई गई।
- भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत 22 भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री विकसित की गई।

निपुण भारत के अंतर्गत सार्वभौमिक एफएलएन

आधारभूत स्तर (कक्षा III) पर दक्षता में सुधार (परख/पीएआरएकेएच, 2024)

- भाषा में 2021 में 39% से बढ़कर 2024 में 57% तक
- गणित में 2021 में 42% से बढ़कर 2024 में 65% तक

शैक्षणिक संरचना एवं पाठ्यक्रम सुधार

- एनईपी द्वारा अनुशंसित 5+3+3+4 संरचना के अनुरूप पाठ्यक्रम सुधार किए गए।
- परख के अंतर्गत दक्षता-आधारित आकलन किए जा रहे हैं।
- डीआईईटी* एवं एससीईआरटी* के माध्यम से शिक्षक क्षमता को सुदृढ़ किया गया है।

शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा

- एपीएएआर* आईडी के माध्यम से विद्यालयी, उच्च एवं कौशल शिक्षा के स्तरों पर शिक्षार्थियों की प्रगति को ट्रैक किया जाता है।
- विद्या समीक्षा केंद्र समय पर हस्तक्षेप हेतु सीखने की प्रगति की निगरानी करता है।

अंतरराष्ट्रीयकरण

- उच्च शिक्षा में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई।
- भारत में 15 विदेशी संस्थानों के कैंपस स्थापित करने की संभावना है।

जीईआर : सकल नामांकन अनुपात; एपीएएआर: स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री; डीआईईटी : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान; एससीईआरटी: राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद; एफएलएन: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना

पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में 37 प्रतिशत की कमी हुई।

वर्ष 2023 में जीवन प्रत्याशा 70.3 थी, जबकि 1976 में यह 49.7 थी।

स्रोत: सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 और एमओएसपीआई।

पोषण सेवन में वृद्धि (प्रति व्यक्ति)

कैलोरी (Kcal/day)

	2009-10	2023-24
Rural	2147	2212
Urban	2123	2240

प्रोटीन (g/day)

	2009-10	2023-24
Rural	59.3	61.8
Urban	58.8	63.4

पोषण सेवन में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी तथा शिशु मृत्यु दर में गिरावट-ये सभी संकेतक मिलकर जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर और समग्र कल्याण में सतत सुधार की ओर संकेत करते हैं।

स्वस्थ जीवनशैली की दिशा में सरकारी पहलें

मोटापे से निपटने हेतु जागरूकता पहलें

- ईट राइट अभियान
- तेल के उपयोग में 10 प्रतिशत की कमी।
- खेलो इंडिया एवं फिट इंडिया आंदोलन।
- आज से थोड़ा कम अभियान।
- स्टॉप ओबेसिटी एवं फाइट ओबेसिटी अभियान।

प्रौद्योगिकी-संचालित पहलें

- एम्स, दिल्ली तथा पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में एआई-संचालित सुधारों हेतु उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना।
- ई-संजीवनी के साथ एकीकृत क्लिनिकल निर्णय सहायता प्रणाली।
- एआई-आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग।
- यू-विन पोर्टल के अंतर्गत 14.32 करोड़ लाभार्थियों का पंजीकरण।

मानसिक स्वास्थ्य: डिजिटल व्यसन से निपटने की पहलें

- विद्यालयों के लिए सुरक्षित इंटरनेट उपयोग संबंधी दिशानिर्देश।
- डिजिटल शिक्षा में स्क्रीन-टाइम योजना हेतु प्रज्ञात फ्रेमवर्क।
- स्क्रीन-टाइम सीमा एवं ऑनलाइन सुरक्षा पर एनसीपीसीआर' के दिशानिर्देश।
- ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम, 2025.
- टेली-मानस* (14416) : 24×7 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन।
- विशेषीकृत उपचार: निम्हांस/एनआईएमएचएएनएस में एसएचयूटी' क्लिनिक।

बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना

1.8 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित, जिनमें कुल 506.50 करोड़ लोगों की कुल उपस्थिति दर्ज की गई।

राज्यों को लगभग 3.78 लाख मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए।

42.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए।

एनसीपीसीआर : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग; टेली-मानस : राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग;
एसएचयूटी : टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग के लिए सेवा;

12 रोजगार और कौशल विकास: उन्नत कौशल की ओर

रोजगार वृद्धि को उत्प्रेरित करना

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए श्रम बाजार की गतिशीलताएँ

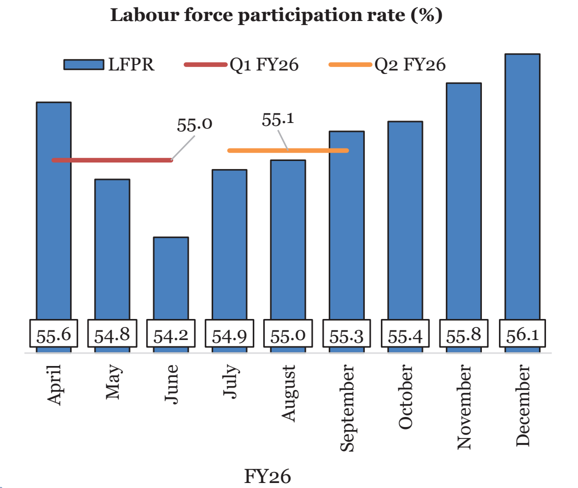

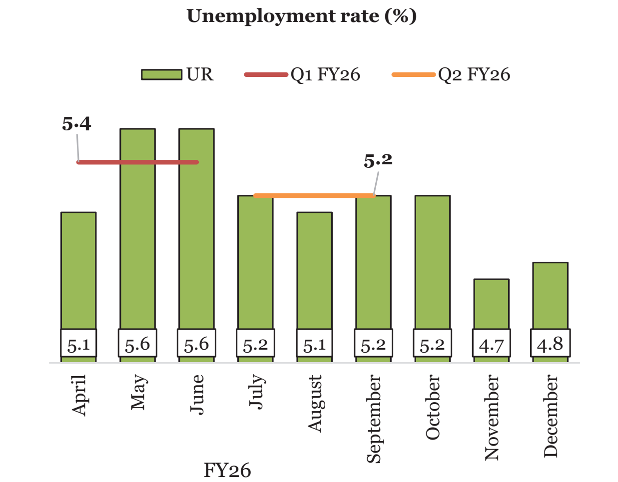

स्रोत: मासिक एवं त्रैमासिक पीएलएफएस बुलेटिन

श्रम संहिताएँ: श्रमिक संरक्षण और लचीलेपन के बीच संतुलन

29 श्रम कानूनों का 4 श्रम संहिताओं में समेकन, जो 21 नवम्बर 2025 को अधिनियमित की गईं-

- **वेतन संहिता, 2019**
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020**
- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020**
- **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020**

औपचारिकता को प्रोत्साहन

- निश्चित अवधि रोजगार (FTE) को औपचारिक रोजगार के रूप में मान्यता
- FTE और संविदा श्रमिकों के लिए समान लाभ
- सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य

उन्नत सामाजिक सुरक्षा

- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से लाभों की पोर्टेबिलिटी
- गिग श्रमिकों को औपचारिक मान्यता

महिला भागीदारी

- क्रेच की व्यवस्था एवं रात्रि पाली को सक्षम बनाना
- मातृत्व लाभ का विस्तार
- लचीले कार्य प्रावधान
- सभी प्रतिष्ठानों में कार्य करने की सुविधा

आय वृद्धि

- वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की शुरुआत
- समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना

व्यापार सुगमता

- 'निरीक्षक' की भूमिका को वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत 'निरीक्षक-सह-सुविधादाता' में परिवर्तित करना, मार्गदर्शन पर विशेष बल
- व्यवसायों के लिए एकल पंजीकरण, एकल रिटर्न और एकल लाइसेंस की व्यवस्था

रोजगार विस्तार

- छंटनी, प्रतिच्छेदन और प्रतिष्ठान बंद करने की सीमा में वृद्धि, ताकि कंपनियाँ छोटे आकार में सीमित न रहें
- प्रशिक्षण एवं भर्ती को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्यक्ष नियुक्ति और थ्र्न का प्रावधान

इसके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लगभग 77 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना (SBI, **नवम्बर 2025**)

महिला भागीदारी बढ़ाना

महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि

2017-18	2023-24
23.3%	41.7%

महिला बेरोजगारी दर में कमी

2017-18	2023-24
5.6%	3.2%

(स्रोत: वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण [PLFS] रिपोर्ट, 2023-24)

लचीली कार्य संरचना

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (CSS) के अंतर्गत लचीले कार्य मॉडल तथा लैंगिक-संवेदनशील कार्य मानकों का प्रावधान।

सुलभ आवास

- सखी निवास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- थोझी छात्रावास, तमिलनाडु

सार्वजनिक-निजी भागीदारी

सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं कौशल विकास

- तेलंगाना का WE-Hub
- महाराष्ट्र का महिला आर्थिक विकास महामंडल
- केरल का कुदुम्बश्री

कौशल विकास

- कौशल प्रशिक्षण को उद्योग की मांग के अनुरूप संरेखित करना
- STEM पाठ्यक्रमों में नामांकन को बढ़ावा
- 'बैक टू वर्क' और 'रिटर्नशिप' जैसे पहल कार्यक्रम केयर अर्थव्यवस्था

शहरी गतिशीलता में सुधार

सुरक्षा अवसंरचना का विस्तार

- कोच्चि का महिला पुलिस नियंत्रण कक्ष
- हैदराबाद की SHE Team
- चेन्नई का समावेशी सड़क डिजाइन मैनुअल
- भुवनेश्वर की जनपथ स्ट्रीट

वैधानिक प्रतिबंधों को हटाना

- 17 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में खतरनाक उद्योगों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध हटाया गया
- 22 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में कारखानों में महिलाओं को रात्रि कार्य की अनुमति
- 33 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात्रि कार्य की अनुमति

केयर अर्थव्यवस्था

- आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार
- सीएसएस के अंतर्गत क्रेच की व्यवस्था

कौशल विकास को सही दिशा देना

उद्योग-प्रेरित कौशल विकास

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय योजना

- 1,000 आईटीआई का उन्नयन
- स्मार्ट कक्षाएँ, आधुनिक प्रयोगशालाएँ, डिजिटल सामग्री तथा उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।

फ्लेक्सी-एमओयू योजना

- कंपनियों द्वारा अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- प्रतिष्ठित उद्यमों द्वारा लगभग 10,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

पीएमकेवीवाई 4.0

- एनएसक्यूएफ-संरेखित जॉब रोल्स में प्रशिक्षण
- उद्योग-नेतृत्व वाले सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ सहयोग
- रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले, जो नियोक्ताओं को नौकरी तलाशने वालों से जोड़ते हैं

कौशल विकास के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण

एनएपीएस 2.0 और एनएटीएस 2.0 के तहत डीबीटी**

- एनएटीएस 2.0 के तहत 12 लाख से अधिक डीबीटी स्टाइपेंड अंतरण किए गए।
- एनएपीएस 2.0 के अंतर्गत स्टाइपेंड का 25 प्रतिशत भाग डीबीटी के माध्यम से सीधे प्रशिक्षुओं को अंतरित किया गया।

कौशल वाउचर

शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करने वाला मांग-पक्ष वित्तपोषण साधन

- महाराष्ट्र विकल्प स्किल वाउचर कार्यक्रम
- तमिलनाडु कौशल वाउचर योजना

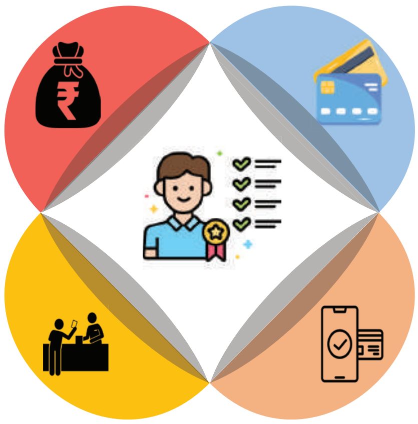

आदर्श कौशल ऋण योजना

- ऋण-आधारित कौशल विकास का विस्तार, ऋण सीमाएँ बढ़ाकर और पात्र ऋणदाताओं के दायरे को विस्तृत करके किया गया।
- एमएसडीई-एसआईडीएच में पंजीकृत प्रदाताओं द्वारा संचालित गैर-एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों तक कवरेज का विस्तार किया गया।

एनएसडीसी का कौशल प्रभाव बॉन्ड*

सत्यापित नियोजन (प्लेसमेंट) और प्रतिधारण परिणामों के साथ वित्तपोषण को जोड़ता है।

एनएसडीसी: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; **डीबीटी:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण; **एनएपीएस:** राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना; एनएटीएस: राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना; एनएसक्यूएफ: राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा; **एसआईडीएच:** स्किल इंडिया डिजिटल हब; **पीएमकेवीवाई:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

13 ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगतिः भागीदारी से साझेदारी तक

गरीबी के विरुद्ध भारत की प्रगति

संशोधित अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा, जो प्रति दिन 3.0 अमेरिकी डॉलर है, के अनुसार वर्ष 2022-23 में अत्यधिक गरीबी दर घटकर 5.3% रह गई।

अवसंरचना

- ग्रामीण संपर्कता में सुधारः 99.6 % से अधिक पात्र बस्तियों को संपर्कता प्रदान की गई है।
- हर घर जलः 81 % से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्राप्त है।
- सभी के लिए आवासः 2.9 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण किया गया।

प्रौद्योगिकी-प्रेरित पहलें

- एसवीएएमआईटीवीए के अंतर्गत 3.28 लाख गाँवों का मैपिंग किया गया; 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए गए।
- नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनानाः 500 ड्रोन दिए गए (2023-24)
- स्मार्ट गाँवों के लिए प्रौद्योगिकी, ड्रोन, सौर ऊर्जा एवं टेलीमेडिसिन का उपयोगः रूटेज स्मार्ट विलेज केंद्र।

कौशल विकास

- डीडीयू-जीकेवाईः ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए राज्य-नेतृत्वित कौशल कार्यक्रम, जो रोजगार, प्रतिधारण, प्रगति तथा तृतीय-पक्ष गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर केंद्रित है।
- आरएसईटीआई के माध्यम से कौशल उन्नयनः 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 616 जिलों में 629 कार्यशील केंद्र।

सहभागी बजट

- प्रभावी कर संग्रह के लिए समर्थ एप्लिकेशन
- निगरानी के लिए मेरी पंचायत ऐप
- ई-ग्राम स्वराजः पंचायत गतिविधियों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग के लिए एकीकृत इंटरफेस।

सामाजिक पूंजी का उपयोग

- डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला-नेतृत्वित एसएचजीके माध्यम से स्वरोजगार और कुशल मजदूरी कार्य के लिए सहायता प्रदान की गई।
- 9 लाख से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति परिवारों की खाद्य सुरक्षा और स्थिर आय की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

*__डीडीयू-जीकेवाईः__ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
डीएवाई-एनआरएलएमः दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
आरएसईटीआईः ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

14 भारत में एआई व्यवस्था/पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) का विकास: आगे की दिशा

एआई पारिस्थितिकी तंत्र: भारत के लिए लाभ और हानि के बीच संतुलन

नीतिगत विकल्पों के लिए बाधाओं को दूर करना

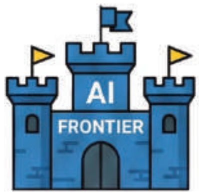

एआई फ्रंटियर

कुछ कंपनियाँ; अधिक एआई क्षमता

सीमांत बनाम अनुप्रयोग के बीच संतुलन: पैमाना और नियंत्रण या स्थानीय सरेखण?

क्षेत्र-विशिष्ट समाधान; विविध प्रकार की कंपनियाँ

एआई अनुप्रयोग

रेपिड स्केल

लागत में कमी; उच्च उत्पादकता

विस्तार बनाम समावेशन: उत्पादकता या अवशोषण?

श्रम वृद्धि; धीमी प्रसार

समावेशन

स्वामित्व

नवाचार के लिए प्रोत्साहन; सीमाओं को आगे बढ़ाना

मालिकाना बनाम ओपन ट्रेड-ऑफ: प्रतिस्पर्धी बढ़त या खुलापन

साझा नवाचार; अनुकूलनशीलता

ओपन-सोर्स

कंप्यूट स्केल

बड़े मॉडल; शक्तिशाली कंप्यूटिंग की उपलब्धता

डेटा सेंटर स्केल बनाम लोकल कंप्यूट ट्रेड-ऑफ: सेंट्रलाइज्ड स्केल या डिस्ट्रीब्यूटेड एफिशिएंसी

छोटे मॉडल; विकेन्द्रीकृत कंप्यूट

स्थानीय गणना

विनियमन

निश्चित लागत और अनुपालन; सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण

विनियमन बनाम नवाचार: सुरक्षा और विश्वास या नवाचार को बनाए रखना

गति; प्रसार; दुरुपयोग के संभावित जोखिम

नवाचार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मानव पूंजी

भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाना:

शिक्षा और काम को फिर से परिभाषित करना

उच्च विद्यालय

अर्जन और अधिगम
(शिक्षुता, परियोजनाएं)

विश्व विद्यालय

लचीले, एकीकृत और क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम कम उम्र से ही शुरू हो जाते हैं, जिससे शिक्षा के साथ-साथ अनुभव भी बढ़ता है।

सफेदपोश नौकरियों से परे: उच्च कौशल और मानव-केंद्रित नौकरियों में मौजूद कमियों को दूर करना

उच्च विद्यालय

धातु कर्म

प्रारंभिक शिक्षा

पाक कला

उच्च क्षमता वाले, कम कर्मचारियों वाले सेक्टर जिन्हें प्रैक्टिकल विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

भविष्य-उन्मुख प्रणाली

सिर्फ संज्ञानात्मक विशेषज्ञता के बजाय अनुभव और लचीलेपन पर जोर देना।

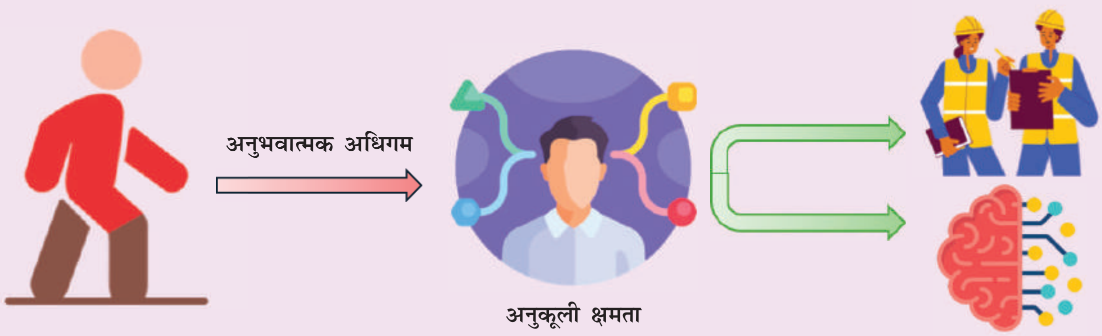

एआई बदलावों के प्रति
लचीला

डेटा एक रणनीतिक संसाधन के रूप में: भारत का एआई युग ढांचा

विश्वसनीय सीमा-पार प्रवाह और घरेलू मूल्य प्रतिधारण

संदर्भ: भारत का डिजिटल पैमाना

1. खुलेपन, नवाचार और निवेश प्रवाह को बनाए रखना

परिसंपत्ति: भारी मात्रा में मानव-जनित डेटा

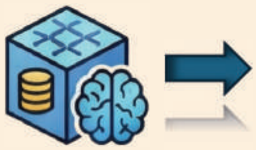

डेटा लोकलाइजेशन फ्रेमवर्क के तीन मुख्य उद्देश्य

1. खुलेपन, नवाचार और निवेश प्रवाह को बनाए रखना

2. निरीक्षण लेखापरीक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करना

3. घरेलू मूल्य बनाए रखना, भारत की एआई क्षमताओं का निर्माण करना।

घरेलू डेटा से मूल्य प्रतिधारण महत्वपूर्ण है।

भारत की विकासात्मक चुनौतियों को हल करने के लिए घरेलू डेटा का उपयोग करना

1. स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि से प्राप्त डेटा, क्षेत्र-विशिष्ट मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए मूल्यवान कारक इनपुट (फैक्टर इनपुट) हैं

2. कुशल प्रतिभा की उपलब्धता में मौजूद कमियों को पूरा करने, मौजूदा कर्मचारियों की उत्पादकता बढाने और भारत की चुनौतियों का जमीनी स्तर से समाधान करने के लिए, क्षेत्र-विशिष्ट एआई की आवश्यकता है।

घरेलू मूल्य सृजन के लिए मेनू-आधारित अनुपालन विकल्प

मॉडलों का स्थानीय प्रशिक्षण

अपस्किलिंग

घरेलू अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय अंशदान

प्रोत्साहनों के माध्यम से विनियमन

सकारात्मक प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करना

लाभ :
घरेलू क्षमता में योगदान -झ ऑडिट में कमी, त्वरित मंजूरी

राज्य लीवर:
सरकारी डेटासेट और प्रोत्साहनों तक पहुंच

15 नागरिक-केंद्रित शहरीकरणः भारतीय शहरों की अगली चुनौती

समूह अर्थव्यवस्थाएं शहरीकरण के तर्क का आधार हैं।

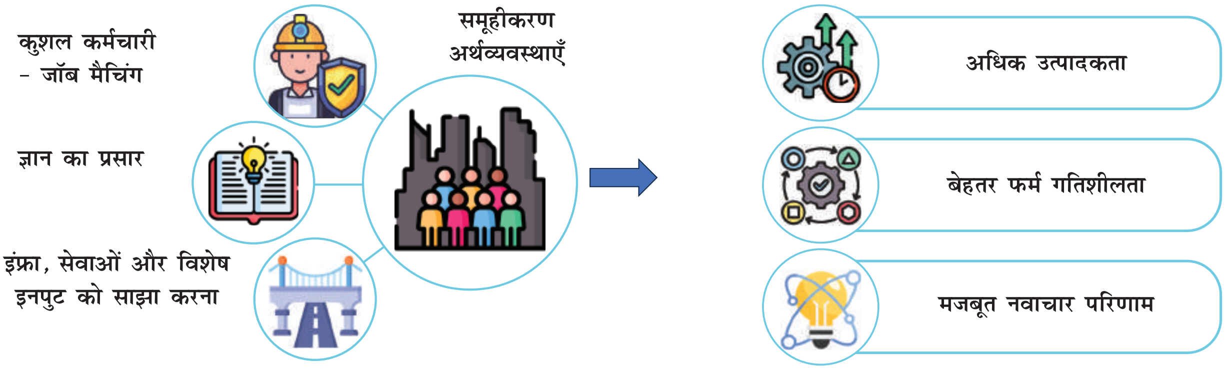

पूरे भारत के शहरों में फ्री एफएसआई ’ दुनिया के बड़े शहरों की तुलना में कम है।

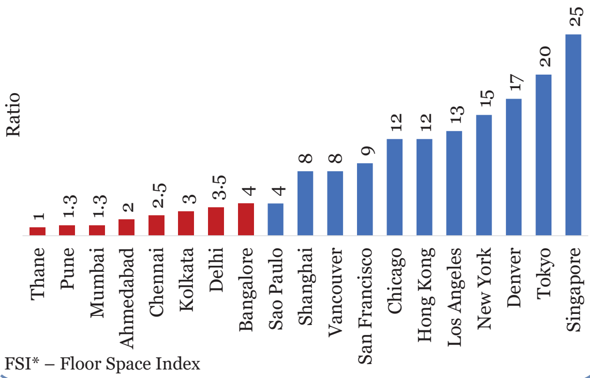

FSI* – Floor Space Index

जमीन की उत्पादकता बढ़ाने से शहरी फैलाव कम करने में मदद मिलेगी

शहरों में बड़े पैमाने पर एफएसआई में वृद्धि करना

लेन-देन को सुगम बनाने के लिए भूमि स्वामित्व प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में भू-आधार और राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शामिल हैं।

विकास नियंत्रण नियमों में ढील देने के साथ-साथ आवागमन, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना आवश्यक है।

गतिशीलता संबंधी समस्याओं से निपटें

2024 में, बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली में यात्रियों को व्यस्त समय के दौरान क्रमशः 117 घंटे, 103 घंटे और 76 घंटे का नुकसान हुआ।

हाल के वर्षों में, भारत में सार्वजनिक परिवहन में भारी विस्तार देखने को मिला है ख मेट्रो, आरआरटीएस और ई-बसें।

परिणामों में सुधार हेतु उपाय

- बस बेड़े को बढ़ाएं और उसका डिजिटलीकरण करें
- वित्त-केंद्रित ई-बस तैनाती
- मुख्यधारा की अंतिम-मील और साझा गतिशीलता
- पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) और स्टेशनों के आसपास मूल्य प्राप्ति
- भीड़भाड़ मूल्य निर्धारण और पार्किंग प्रबंधन के माध्यम से उन क्षेत्रों में मांग को नियंत्रित करें जहां भौगोलिक स्थिति सबसे अधिक बाध्यकारी है।

अपशिष्ट प्रबंधन में सरकारी उपायों से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

- घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का संग्रहण: 2014-15 में नगण्य; 2024-25 में शहरी वार्डों के 98% हिस्से को कवर करता है।
- देशभर में 2.5 लाख कचरा संग्रहण वाहन
- संग्रह मार्गों की निगरानी के लिए कई शहरों में जीपीएस-सक्षम वाहन और एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण: 2014-15 – 16% नेतृत्व बाइ -इन 2024-25 – 80%

अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन - इंदौर का मामला

भारत का सबसे स्वच्छ शहर - इंदौर

- अलगाववादी प्रथाओं को सुदृढ़ करना
- परंपरागत एवं आधुनिक संचार-नुक्कड़ नाटक, रेडियो शो, आदि
- स्कूली छात्रों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह
- नेतृत्व बाइ -इन
- धार्मिक और स्थानीय नेताओं ने एकजुटता दिखाई
- कठोर दंड

सामाजिक व्यवस्था और नागरिक भावना का विकास करना

- शहरों को नियमों की संख्या बढ़ाने के बजाय नियमों की निश्चितता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- शहरी डिजाइन और सर्विस डिलीवरी को व्यवहारिकसाधनों के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए
- इंसेंटिव सही व्यवहार के हिसाब से होने चाहिए।
- नागरिक भावना के बारे में सामाजिक अनुबंध को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार संबंधी तरीकों का उपयोग करना
- एपिसोडिक मैसेजिंग के बजाय सिस्टम-आधारित नागरिक-बोध जागरूकता
- नागरिक व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों में शहरी नियमों के वितरण पहलू को पहचानना जरूरी है।

भविष्य के शहरों के गैर-भौतिक पहलू

- **समय एक केंद्रीय शहरी संसाधन के रूप में**
- सामाजिक अवसंरचना के रूप में सड़कें
- रचनात्मक घनत्व को प्रोत्साहित करना
- अनौपचारिकता का एकीकरण
- ऐसा शासन जो भागीदारी को सक्षम बनाता है
- ऐसे शहर जो कल्पना को प्रेरित करते हैं